A Daily News Magazine
भोपाल
बुधवार, 4 सितम्बर , 2024

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष -22 अंक-7 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रू.- 2 (डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

सिखों के गुस्से के बाद कंगना पर फिल्म 'इमरजेंसी' में बदलाव का दबाव

शंकर अर्निमेष

यह सिर्फ सिख समुदाय के बीच व्यापक आक्रोश, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की ओर से प्रोडक्शन हाउस को कानूनी नोटिस या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की ओर से विरोध ही नहीं था, जिसके कारण केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' में और बदलाव करने को कहा। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के नेताओं की ओर से दी गई चेतावनी ने भी इसमें भूमिका निभाई। सूत्रों ने बताया कि भाजपा पंजाब के महासचिव जगमोहन सिंह राजू ने इस सप्ताह सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखकर फिल्म को प्रमाण पत्र देने से पहले इसकी विषय-वस्तु की बेहतर तरीके से जांच करने का अनुरोध किया। सूचना मंत्रालय ने पहले ही फिल्म को न्यूनतम कट के साथ मंजूरी देने के बावजूद प्रमाणन रोक दिया है। भाजपा के एक सूत्र ने कहा, 'बोर्ड ने कंगना की टीम को और अधिक बदलाव करने का निर्देश दिया है और सिख समुदाय की आपत्तियों के बाद किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचने के लिए फिल्म की सामग्री की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रहा है।'

रनौत पहले से ही किसानों के विरोध प्रदर्शन पर अपनी विभिन्न विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही थीं, खासकर चुनावी राज्य हरियाणा में- जहां भारतीय किसान यूनियन ने उन्हें माफ़ी मांगने या परिणाम भुगतने की चेतावनी जारी की थी। इसके कारण भाजपा ने उनके बयानों से खुद को दूर कर लिया है। हरियाणा की आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत है।

शुक्रवार को रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके खुलासा किया कि फिल्म का प्रमाणन रोक दिया गया है। उन्होंने वीडियो में हिंदी में कहा, 'अफवाहें फैल रही हैं कि मेरी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया है। यह सच नहीं है। हमारी फिल्म को सीबीएफसी से मंजूरी तो मिल गई, लेकिन सेंसर बोर्ड के सदस्यों को जान से मारने की कई धमकियों के कारण प्रमाणन में देरी हुई। इससे हम पर दबाव पड़ा है कि हम फिल्म में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या, (सिख आतंकवादी जरनैल सिंह) भिंडरावाले और पंजाब दंगों को न दिखाएं। इससे सवाल उठता है कि मैं फिल्म में वास्तव में क्या दिखा सकती हूं? क्या फिल्म को अचानक ब्लैक आउट कर देना चाहिए? यह मेरे लिए अविश्वसनीय समय है और मुझे इस देश की स्थिति पर दुख है।'

शुक्रवार को सीबीएफसी की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, फिल्म को कुछ संशोधनों के बाद पहले ही मंजूरी दे दी गई थी, जिसमें धूम्रपान पर चेतावनी जोड़ने, 'एक सार्वजनिक नेता की मृत्यु' के बाद भीड़ द्वारा चिल्लाए गए 'अपमानजनक' शब्द को म्यूट करने और 'मिस्टर प्रेसिडेंट' शब्द को हिंदी संस्करण 'राष्ट्रपति जी' से बदलने की आवश्यकता शामिल थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बयान और ऑपरेशन ब्लू स्टार के अभिलेखीय फुटेज वाले खंडों के लिए, अन्य चीजों के अलावा, सीबीएफसी ने दस्तावेज मांगे हैं।

फिल्म के ट्रेलर ने विवाद की शुरुआत तब की जब इसमें मारे गए आतंकवादी भिंडरावाले को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ काम करते हुए दिखाया गया, जिसमें उन्होंने अलग सिख राज्य के बदले में कांग्रेस पार्टी के लिए वोट लाने का वादा किया था। 14 अगस्त को ट्रेलर रिलीज़ होने के तुरंत बाद सिख संगठनों ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने सिख प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की और उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य फिल्म पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है। शिअद की दिल्ली इकाई ने शुक्रवार को रनौत के प्रोडक्शन हाउस को कथित तौर पर गलत ऐतिहासिक तथ्य दिखाने के लिए कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में शिअद (दिल्ली) प्रमुख परमजीत सिंह सरना ने लिखा, 'आपातकाल के दौरान शिअद सरदार हरचंद सिंह लोंगोवाल ने आपातकाल का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिल्म ऐसे योगदानों की उपेक्षा करती है और इसके बजाय सिख समुदाय को नकारात्मक और अन्यायपूर्ण तरीके से चित्रित करती है। इस तरह के चित्रण न केवल भ्रामक हैं, बल्कि पंजाब और राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने के लिए बेहद अपमानजनक और नुकसानदेह भी हैं। यह स्पष्ट है कि कंगना, जो अपने सिख विरोधी रुख के लिए जानी जाती हैं, ने इस विषय को कांग्रेस के खिलाफ वास्तविक राजनीतिक या ऐतिहासिक बयान देने के लिए नहीं बल्कि सिख समुदाय को निशाना बनाने के लिए चुना है।'

पंजाब भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा- 'हम फिल्म के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि पार्टी को उम्मीद थी कि आपातकाल पर बनी फिल्म कांग्रेस को खराब तरीके से दिखाएगी जिससे बीजेपी के प्रति अच्छी धारणा बनने से पार्टी को लाभ मिलेगा। लेकिन फिल्म में कुछ दृश्य जो सिख समुदाय पर आक्षेप लगाते हैं, वे पार्टी के लिए अच्छे नहीं हैं। इस तरह के चित्रण न केवल भ्रामक हैं, बल्कि पंजाब और राष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने के लिए बेहद अपमानजनक और नुकसानदेह भी हैं। यह कंगना ने इस विषय को सिख समुदाय को निशाना बनाने के लिए चुना है।'

एसपीजीसी के बयान ने भी पार्टी पर दबाव बढ़ा दिया है। एसजीपीसी सदस्य गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि 'संत जरनैल सिंह भिंडरावाले सिख धर्म में एक उच्च स्थान रखते हैं और उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति माना जाता है। हम इस फिल्म में सिख समुदाय को जिस तरह से दिखाया गया है, उसका कड़ा विरोध करते हैं। फिल्म के ट्रेलर में स्पष्ट रूप से सिखों को एक अनुचित, क्रूर और हिंसक समुदाय के रूप में दिखाया गया है।'

अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भाजपा से फिल्म पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा और सिख समुदाय को जिस तरह से दिखाया गया है, उसे लेकर अभिनेत्री की आलोचना की। उन्होंने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह (कंगना) भाजपा की सांसद हैं और भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह जो कुछ भी दिखा रही हैं, क्या वह इस मुद्दे पर पार्टी का रुख है। हरसिमरत के अनुसार, उनके ससुर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल देश का पहला राजनीतिक संगठन था, जिसने 1975 के आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। बादल आपातकाल लागू करने का विरोध करने वाले पहले लोगों में से थे और हर दिन शिरोमणि अकाली दल का एक जत्था गिरफ्तारी देता था।'

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

डिफेंस पार्टनरशिप से लेकर समुद्री सुरक्षा तक, सब पर होगी चर्चा

- ब्रूनेई पहुंचे पीएम मोदी, सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से की मुलाकात
- सिंगापुर के साथ समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर रहेगा भारत का जोर

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रूनेई दारुस्सलाम और सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा पर दोपहर 3 बजे ब्रूनेई पहुंचे। भारत-ब्रूनेई दारुस्सलाम के राजनयिक संबंधों ने 40 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रूनेई दारुस्सलाम के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से मिलने पहुंचे हैं। पीएम मोदी 4 सितंबर को ब्रूनेई से सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। वहां पहुंचकर वे सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे पर समुद्री सुरक्षा को लेकर बातचीत से चीन की टेंशन बढ़ना तय है। भारत और ब्रूनेई दारुस्सलाम के बीच राजनयिक संबंध 1984 में स्थापित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेल से संपन्न देश ब्रूनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम की इस यात्रा के दौरान रक्षा साझेदारी पर विशेष जोर रहा। इसकी वजह है कि दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र में एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने के इच्छुक हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारत और ब्रूनेई रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, स्पेस टेक्नोलॉजी सहयोग में एक दूसरे से जुड़े हैं।

दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों की नक्सलियों पर बड़ी स्ट्राइक

- अब तक 9 नक्सली ढेर, मुठभेड़ जारी, हथियार भी बरामद

रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अब तक 9 नक्सलियों को मार गिराया है। घटनास्थल से नक्सलियों के शवों के साथ एसएलआर, 303 और 12 बोर के हथियार भी बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बस्तर डिवीजन में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस की संयुक्त टीम सर्चिंग अभियान पर निकली थी। मंगलवार सुबह 10.30 बजे सर्चिंग के दौरान पुलिस पार्टी का सामना पीएलजीए की कंपनी नंबर 02 के नक्सलियों से हुआ, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को कड़ा जवाब दिया और 9 नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से नक्सलियों के शवों के साथ हथियार भी बरामद हुए हैं।

सुप्रभात

मेले-ठेले, हाट, मंडियां
लोक जीवन की यही झलकियां
चली उठी और गांव पहुंच रही
खेड़े देहात की कच्ची पगडंडियां।

थैला झोला भरकर चलते
हाट में रखते ताजी सब्जियां
हरिया, नासिर संग चले हैं
सजे हैं ठिए, धजी मंडियां।

चरमर-चरमर चली है साइकिल
कटा है रस्ता, मन है चंचल
प्यार बंटा है नेह बढ़ा है
आंसु भरकर दुखी है अखियां।

रंग कई हैं ढंग कई हैं
चमक रहीं हैं लाल चूड़ियां
बिंदिया, बिछिया लेकर आई
सासु से मन भर लड़ी है मुनिया।

- सारंग उपाध्याय
लोकरंग

मणिपुर में फिर हमला : लगातार दूसरे दिन ड्रोन अटैक

कुकी उग्रवादियों ने मैतेई इलाके में घरों पर गिराए बम

2 लोग घायल, म्यांमार से टेक्निकल सपोर्ट की आशंका

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर में इंफाल जिले के सेजम चिरांग गांव में सोमवार की शाम उग्रवादियों ने ड्रोन अटैक किए। जिसमें में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह 2 दिन में दूसरा ड्रोन अटैक है। सोमवार शाम करीब 6.20 बजे सेजम चिरांग के रिहायशी इलाके में ड्रोन से 3 विस्फोटक गिराए। जो छत को तोड़ते हुए घरों के अंदर फटे। उग्रवादियों ने पहाड़ी की चोटी से गोलीबारी भी की। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। सेजम चिरांग गांव, कोत्रुक से करीब 3 किमी दूर है, जहां रविवार 1 सितंबर को ड्रोन हमले और गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई थी और 9 लोग घायल भी हुए थे। ये आशंका जताई जा रही है कि कुकी उग्रवादियों को ड्रोन वॉरफेयर के लिए म्यांमार से टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग मिल रही है, या वे सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं। ड्रोन से पहला बम सेजम चिरांग गांव के मानिंग लीकाई में 65 साल के वाथम गंभीर के घर की छत पर बम गिरा, दूसरा बम उसके घर के बगल वाली गली में गिरा, जबकि तीसरा बम नदी के किनारे फटा। वाथम गंभीर की बेटी सनातोम्बी (23) के पेट में छर्रे लगे। उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

सीएम मोहन यादव के पिता पूनमचंद यादव का निधन

उज्जैन। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनमचंद यादव का मंगलवार शाम निधन हो गया। वे 100 वर्ष की आयु के थे और बीते एक सप्ताह से अधिक बीमार थे। फ्रीगंज स्थित अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री उज्जैन के लिए रवाना हो गए। वे करीब 9.30 बजे उज्जैन पहुंचे।

उज्जैन शहर के फ्रीगंज स्थित एसएन कृष्णा अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। रविवार को उज्जैन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री यादव भी अपने पिता का स्वास्थ्य जानने अस्पताल पहुंचे थे। वहीं सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनसे मिले थे।

कपड़ा बनाने वाली मिल में करते थे काम

समाजजन के अनुसार पूनमचंद यादव का जीवन संघर्ष के बीच गुजरा। उन्होंने कपड़ा बनाने वाली हीरा मिल में नौकरी भी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित उनके तीन बेटे और दो बेटियां हैं। पिता के निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री यादव भोपाल से उज्जैन पहुंचे।

नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं

सीएम के पिता के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आदि ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिर से पिता का साया उठ जाना जीवन की अपूरणीय क्षति है।

दुख की इस विकट घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। पूज्य पिताजी भले ही भौतिक रूप से साथ नहीं है, किंतु उनके आशीर्वाद की छांव सदैव आपके साथ है। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। दिग्विजय सिंह ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिता पूनमचंद यादव के निधन की खबर दुःखद है। भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं दुःख की इस घड़ी में परिजनों को संबल प्रदान करें। विनम्र श्रद्धांजलि। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इनके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि पिता का साया सिर से उठना एक पुत्र पर उसके जीवन का सबसे बड़ा वज्रपात होता है। इस खालीपन को कभी भरा नहीं जा सकता। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि मोहन यादव के पिता के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक हैं। बाबा महाकाल शोकाकुल परिजनों को दुःख की इस घड़ी में संबल प्रदान करें।

बच्चों के साड़ी के पल्लू से बांधे पैर, ड्रोन से निगरानी

35 गांव में दहशत, बहराइच में भेड़ियों से बचने के हर इंतजाम हो रहे फेल

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के 35 गांवों के लोग भेड़ियों के खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। इन गांवों में लोग रात-रात भर जागकर घरों की रखवाली कर रहे हैं। इसको लेकर इन गांवों के लोगों ने कुछ इस तरह अपनी आपबीती सुनाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सबकुछ कुछ ही सेकंड में हो गया। सोमवार को सुबह 3 बजे मीरा देवी की नींद अचानक टूटी। अभी भी आधी नींद में ही उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी दो साल की बेटी अंजलि, जो पिछली रात उनके बगल में सोई थी, गायब है। इससे पहले कि मीरा शोर मचा पाती या अपने सोते हुए पति को जगा पाती, भेड़िये अंजलि को लेकर दंपत्ति के बिना दरवाजे वाले ईंट के घर से बाहर निकल चुके थे। दो घंटे बाद, अंजलि का क्षत-विक्षत शव बहराइच जिले के गुरुदत्त सिंह पुरवा गांव के पास के गन्ने के खेत में मिला। पिछले दो महीनों में, छह भेड़ियों का एक झुंड सूर्यास्त के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महासी तहसील के 35 गांवों में लोगों, खासकर बच्चों को अपना निशाना बना रहा है।

भेड़ियों को पकड़ने के लिए 25 टीमें तैनात

पिछले कुछ दिनों में वन अधिकारियों ने 5 किलोमीटर के दायरे में दो भेड़ियों के देखे जाने की सूचना दी है। प्रभावित गांवों में रेंजर, फॉरेस्टर, गार्ड और वॉचर वाली 25 वन टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा, पड़ोसी जिलों के तीन प्रभागीय वन अधिकारी, रेंज और उप-विभागीय वन अधिकारियों के साथ मिलकर जानवरों की गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। जाल और पिंजरे जो बैठे या सोते हुए बच्चे की तरह दिखते हैं उनको रणनीतिक रूप से रखा गया है, थर्मल कैमरों से लैस चार ड्रोन से प्राप्त जानकारी के आधार पर जो वर्तमान में भेड़ियों पर नज़र रख रहे हैं।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 36.3 °c
न्यूनतम 30°c

2

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 4 सितम्बर 2024

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

हेलीकॉप्टर ध्रुव की अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग

अहमदाबाद (एजेंसी)। भारतीय कोस्टगार्ड के हेलीकॉप्टर ध्रुव को अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। इस दौरान हेलीकॉप्टर में सवार इंडियन कोस्ट गार्ड के दो पायलट लापता हो गए हैं। उनके साथ एक ड्राइवर भी सवार था। उसके बारे में भी कोई खबर नहीं मिल पाई है। अब तक मिली जानकारी के

अनुसार एक क्रू मेंबर को बचा लिया गया है, लेकिन बाकी तीन लोग लापता हैं। यह हेलीकॉप्टर गुजरात में आई बाढ़ से जुड़े राहत एवं बचाव कार्य में जुटा था। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों का कहना है कि हेलीकॉप्टर ने सोमवार की रात को पोरबंदर के पास समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग की थीं। इस हेलीकॉप्टर में दो पायलट और दो डाइवर सवार थे। अब तक एक ड्राइवर को बताया जा सका है, लेकिन बाकी तीन लोग अब भी लापता है।

शराब घोटाले में केजरीवाल पर सीबीआई की नई चार्जशीट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एएपी विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ सीबीआई के पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है। इस बारे में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, जिसके बाद उन्होंने

आरोपियों को 11 सितंबर को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी 11 सितंबर तक बढ़ा दी। सीबीआई ने 30 जुलाई को अपना चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट (पूरक आरोपपत्र) दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल, पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष माथुर और पी. सरथ रेड्डी को मामले में आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने चौथी सप्लीमेंट्री पेश की।

60 हजार जवान नहीं ला पा रहे शांति, उन्हें वापस बुलाएं

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने सोमवार को केंद्र से अनुरोध किया कि यदि केंद्रीय बलों की मौजूदगी से हिंसा नहीं रुकती तो राज्य से उनको वापस बुला लिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में सिंह ने कहा कि यदि केंद्रीय बल ऐसा करने में विफल रहते हैं तो जातीय संघर्ष प्रभावित राज्य में शांति बहाल करने के प्रयास के लिए राज्य सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की

अनुमति दी जानी चाहिए। सिंह ने कहा कि मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद शांति नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सिंह, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। उन्होंने कहा, मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी शांति स्थापित नहीं कर पा रही है, इसलिए बेहतर है कि ऐसे बलों को हटा दिया जाए जो ज्यादातर मूकदर्शक के रूप में मौजूद रहते हैं। हाल में असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को वापस बुलाने की कार्रवाई की गई। हम हटाने की कार्रवाई से प्रसन्न हैं।

'निष्क्रिय' लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी कांग्रेस

यूपी में शुरू हो गई है पार्टी के 'कायाकल्प' की तैयारी

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में अब संगठन की नजर ऐसे जिला और शहर अध्यक्षों पर है, जो अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। इनकी छंटनी पर फैसला ले लिया गया है। इन पदों पर बेहतर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को तैनात करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक अगले 10 से 15 दिनों में जिला और शहर अध्यक्षों की लिस्ट नए सिरे से जारी की जाएगी। इन दिनों राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तर तक कांग्रेस के संगठन को चुस्त-दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। बीते दिनों कांग्रेस ने सचिवों की सूची जारी की थी। इसमें यूपी में तैनात रहे सभी 6 सचिवों को फिर से यूपी में ही तैनाती दी गई है। सचिवों की तैनाती के बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और यूपी के सभी 6 सचिवों की बैठक हुई। इसमें संगठन को लेकर चर्चा हुई और तय हुआ है कि जिलों के संगठन की समीक्षा की जाए। जो भी जिला और शहर अध्यक्ष फिलहाल पूरी तत्परता से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिह्नित करके उनकी जगह पर किसी दूसरे को यह जिम्मेदारी दी जाए। सूत्र बताते हैं कि चिह्नांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्द ही इन लोगों की जगह पर नए जिला और शहर अध्यक्षों के नाम तय किए जाएंगे।

● प्रदेश कमेटी में भी शामिल हो सकते हैं कुछ और लोग

जिला और शहर अध्यक्ष तय होने के बाद प्रदेश कमिटी में भी कुछ और लोगों को शामिल करने की तैयारी है। सूत्र बताते हैं कि पहले से शामिल रहे लोगों को की जिम्मेदारी बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। कांग्रेस की मंशा है कि विधान सभा उपचुनाव के पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। हालांकि नेतृत्व की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बदलाव किए जा सकते हैं लेकिन इससे उप चुनाव की तैयारियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लिहाजा उप चुनाव की तारीखें अगर हाल फिलहाल घोषित नहीं होती हैं तो बदलाव की प्रक्रिया उसके पहले ही हो जाएगी। अगर उप चुनाव की तारीखें प्रक्रिया के पहले ही आ जाती हैं तो उप चुनाव तक इन बदलावों को टाला जा सकता है। कांग्रेस यूपी को लेकर काफी अलर्ट है। लोकसभा चुनाव से उसे संजीवनी मिली है।

आप-कांग्रेस हरियाणा में भी साथ लड़ेंगे चुनाव!

● गठबंधन के मूड में हैं राहुल गांधी, जल्द होगा फैसला

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन खबरें हैं कि सांसद राहुल गांधी आप के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इस संबंध में उन्होंने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं से बात भी की है। इससे पहले आप और कांग्रेस दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई क्षेत्रों में साथ मिलकर मैदान में उतर चुकी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं। रिपोर्ट के

अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से आप संग गठबंधन की संभावनाओं पर राय भी पूछी थी। हालांकि, अब तक इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इससे पहले एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया था।

सीएम मोहन यादव मिस्ड कॉल से बने भाजपा के सदस्य

कहा-जब से हमारी सरकार बनी, हमने प्रयास किया कानून सबके लिए बराबर हो

भोपाल। मध्यप्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान मंगलवार से शुरू हो गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मिस्ड कॉल देकर भाजपा की सदस्यता ली। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा- मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं। जिस तरह से सूर्य-चंद्रमा के अथक परिश्रम की वजह से पूरी सृष्टि आनंद में डूबती हैं, उसी तरह हमारे संगठन की प्रणाली है। जब से हमारी सरकार बनी हमने यह प्रयास किया कि कानून सबके लिए बराबर हो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि उसके बाद हमने 22000 माइक उतारने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। प्रदेश के किसी जिले में कोई गंभीर बीमार हो तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। पुरानी सरकार में हेलिकॉप्टर घर में खड़ा होता था। हमने तो गरीब के लिए हेलिकॉप्टर खड़ा कर दिया। उप चुनाव में लोग अमरवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ कह रहे थे। हमने कहा था गढ़ नहीं वो गड़बड़ है। हमने ढोल की पोल पकड़ ली। आने वाले सब चुनाव भी जीतेंगे। अकेले चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं है, एक-एक राष्ट्र भक्त को भाजपा से जब तक नहीं जोड़ेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे।

कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में इतिहास बनाएंगे- प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा- आज सदस्यता अभियान के शुभारंभ में सभी जिलों से लेकर बूथों तक कार्यकर्ता जुड़े हैं। 8800002024 मिस्ड कॉल नंबर पर सदस्य बन सकते हैं। आज ही इतने ज्यादा लोग सदस्य बनने के लिए उत्साहित हैं। देश में 1 करोड़ 31 लाख लोगों ने कुछ ही समय में सदस्यता फॉर्म भरा। जब अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष बने थे, तब चाइना की राजनीतिक दल के सबसे ज्यादा सदस्य हुआ करते थे। आज 11 करोड़ सदस्य बनाकर हम दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल हैं। 2019 में भाजपा के 18 करोड़ सदस्य बने। एमपी में 64871 बूथों का कार्यकर्ता सदस्यता अभियान में इतिहास बनाएंगे।

एमपी में डेढ़ करोड़ नए लोगों को जोड़ने का टारगेट

25 सितंबर तक सदस्यता अभियान के पहले चरण में बीजेपी देश भर में 10 करोड़ नए लोगों को सदस्य बनाएगी। वहीं, एमपी में डेढ़ करोड़ नए लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान शिक्षक दिवस पर निजी शिक्षकों को सदस्यता दिलाने के लिए बीजेपी ने शिक्षक प्रकोष्ठ को दिशा निर्देश दिए हैं। बीजेपी ने सांसदों, मंत्रियों विधायकों से लेकर हर पदाधिकारी को सदस्यता का लक्ष्य दिया है। एमपी में सांसदों को 25 हजार नए सदस्य बनाने होंगे। विधायकों को 15 हजार नए लोगों को मैंबरशिप दिलानी होगी। ऐसे ही जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों को भी टारगेट दिया गया है।

वेस्ट बंगाल विधानसभा में पास हुआ एंटी रेप बिल 'अपराजिता'

● पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी होगी

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। भाजपा ने भी बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप-मर्डर हुआ था। इसके बाद देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राज्य में रेप जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार चिट्ठी लिखी थी। इस बिल के अनुसार, रेप और हत्या करने वाले आपराधी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस को 21 दिनों जांच पूरी करनी होगी। इस बिर में दरिंदगी करने वाले के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजा-ए-मौत का प्रावधान है। इस बिल में अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान है।

तेलंगाना-आंध्र में बारिश ने दिखाया रौद्र रूप

● 100 से ज्यादा गांव और शहर डूबे, कई ट्रेनें हुईं रद्द ● बारिश-बाढ़ से 33 लोगों की मौत, गुजरात में रेड अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ आ गई है। दोनों राज्यों में अब तक 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें 17 लोग आंध्र और 16 तेलंगाना के थे। सोमवार (2 सितंबर) की दोपहर तक लगभग 432 ट्रेनें कैंसिल की गईं। 139 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में यह सबसे बड़ी त्रासदी देखी है। हुदहुद और तितली साइक्लोन की तुलना में पिछले तीन दिनों की बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य में करीब 4.5 लाख लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के सूरत और भरूच जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट है। आईएमडी ने अगले 3 दिनों में गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आंध्र प्रदेश में करीब 4.5 लाख लोग बारिश और बाढ़ से प्रभावित हैं। विजयवाड़ा, एनटीआर, गुंटूर, कृष्णा, एलुरु, पालनाडु, बापटला और प्रकाशम में हालात सबसे बुरे हैं। एनडीआरएफ की 20 और एसडीआरएफ की 19 टीमें राहत और बचाव में लगी हैं। विजयवाड़ा में 24 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली गुल रहने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में यह सबसे बड़ी त्रासदी देखी है। हुदहुद और तितली साइक्लोन की तुलना में पिछले तीन दिनों की बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। सीएम नायडू ने बताया कि हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, नावों, ट्रैक्टरों और वैन के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तेलंगाना सरकार ने सोमवार को बताया कि बारिश-बाढ़ से राज्य को कुल 5438 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 110 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इनमें 4000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। लगातार बारिश के कारण खम्मम के प्रकाश नगर में मुन्नरू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खम्मम के कलेक्टर मुजम्मिल खान ने कहा कि पिछले 30 सालों में ऐसी बाढ़ नहीं आई है।

जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ा रहा चीन!

राजनीतिक उथल-पुथल का उठाना चाहता है फायदा, भारत के लिए बनेगा खतरे की घंटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल ही में हुए राजनीतिक उथल-पुथल के बाद दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक परिदृश्य बदलता नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने जहां पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के संकेत दिए हैं, वहीं चीन ने अब बांग्लादेश पर डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने सोमवार को वहां की राजनीतिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी के दफ्तर जाकर पार्टी प्रमुख शफीकुर रहमान से मुलाकात की है। चीन ने भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया हो लेकिन यह मुलाकात इस मायने में अहम है क्योंकि मार्च 2010 में जमात के खिलाफ युद्ध अपराधों का मुकदमा शुरू होने के बाद पहली बार किसी राजनयिक ने ढाका स्थित जमात-ए-इस्लामी के दफ्तर का दौरा किया है। पुलिस ने 2011 में जमात का दफ्तर सील कर दिया था लेकिन इस साल शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए छात्र विद्रोह और हसीना सरकार की बेदखली के बाद इसे फिर से खोल दिया गया है। सोमवार को चीनी राजदूत ने शफीकुर रहमान से मुलाकात के बाद उनकी पार्टी के बांग्लादेश की एक सुव्यवस्थित पार्टी करार दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को एक खूबसूरत देश भी करार दिया। वेन ने कहा कि चीन बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। दरअसल, शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा था, जबकि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। हालांकि, 2014 से 2018 के बीच शेख हसीना के चीन के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। चीन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और जमात-ए-इस्लामी जैसे राजनीतिक दलों के साथ भागीदारी और द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर जोर दे रहा है। शिक्षा, संस्कृति और विकास परियोजनाओं के मुद्दे पर चीन बांग्लादेश की मदद करना चाह रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह बांग्लादेश की भौगोलिक अवस्थिति है। बांग्लादेश भारत से सटा हुआ देश है।

छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों का कमाल, 9 नक्सली किए ढेर

● दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर 13 घंटे चली मुठभेड़; मारे गए नक्सलियों के शव, हथियार-विस्फोटक बरामद

जगदलपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा-बीजापुर बॉर्डर पर मंगलवार को सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया है। जवानों ने मारे गए नक्सलियों के शव और स्रूक्र राइफल, 303 और 315 बोर राइफल, विस्फोटक बरामद किया है। मुठभेड़ किरंदुल थाना क्षेत्र में बैलाडीला के जंगल में हुई। बताया जा रहा है कि करीब 13 घंटे तक मुठभेड़ चली है। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में शामिल सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अफसरों के मुताबिक, ज्यादा जानकारी जवानों के लौटने के बाद ही मिलेगी। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, जवानों की भुजाओं की ताकत है, जिसके आगे पूरा बस्तर शांत होने वाला है। दंतेवाड़ा जिले के एसपी गौरव राय ने बताया कि, बैलाडीला की पहाड़ियों के नीचे पुरंगेल, लोहा गांव की तरफ पश्चिम बस्तर डिवीजन के माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी।

'पेसा एक्ट' के तहत ग्राम सभा सशक्तिकरण के प्रयास जरूरी : राज्यपाल मंगुभाई पटेल

राज्यपाल बोले-विकास की गति के लिए पर्यवेक्षण,निरीक्षण,अन्वेषण जरूरी

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि पेसा अंतर्गत ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने के लिए उनको हैन्ड होल्डिंग सपोर्ट उपलब्ध कराने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाना चाहिए। सभी ग्राम सभाओं द्वारा पेसा एक्ट के प्रावधानों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जाए। समुदाय विकास के पथ पर समान रुप से सबके साथ आगे बढ़े। इस संबंध में जन-जागृति के साथ जन-जागरण के लिए विभागीय स्तर पर पहल की जानी चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में आयोजित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में चर्चा कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह भी मौजूद थी। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा है कि विकास की गति बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षण निरीक्षण और अन्वेषण के कार्यों की निरंतरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्माण कार्य के निरीक्षण के साथ ही आवंटित राशि के उपयोग का पर्यवेक्षण जरूरी है। साथ ही आवास की डिजाइनिंग, हवा और रोशनी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए जमीनी हकीकतों और व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधानों का अन्वेषण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि पेसा एक्ट के तहत ग्रामसभा के सशक्तिकरण प्रयासों पर विशेष बल दिया जाए। ग्राम सभाओं को उनके अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। जरूरी है कि ग्रामसभा सशक्तिकरण के कार्य सकारात्मक दृष्टिकोण और नवीन विचारों के साथ योजनाबद्ध ढंग से किए जाएं। राज्यपाल श्री पटेल ने टी.बी. उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति वर्ष 2025 तक करने के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ प्रयासों की जरूरत बताई। क्षय रोगियों को पोषण आहार की उपलब्धता के लिए निःक्षय मित्र योजना को विस्तारित करने के लिए कहा है। इस कार्य में व्यापारिक और व्यावसायिक संगठनों के साथ समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास प्रयासों पर चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम. जनमन) अभूतपूर्व पहल है। योजना की मंशा विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन को खुशहाल बनाना है। योजना की सफलता के लिए जरूरी है कि संवेदनशील दृष्टिकोण और गुणात्मक गुणवत्ता के साथ विकास के कार्य किए जाएं। बैठक में राज्यपाल श्री पटेल को बताया गया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश में पहली सड़क और आवास पूर्ण करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। विभाग द्वारा निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) भी तैयार कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मलय श्रीवास्तव, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री मुकेश चंद गुप्ता, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, संचालक पंचायतराज श्री मनोज पुष्प एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

125 सीएम राइज स्कूलों में निःशुल्क परिवहन सेवा

प्रदेश के करीब 70 हजार विद्यार्थियों को मिल रही है सुविधा

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये विभिन्न जिलों में पहले चरण में 275 सीएम राईज स्कूल शुरू किये है। इनमें से 125 सीएम राईज स्कूलों में 70 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क परिवहन सेवा की सुविधा दी जा रही है। निःशुल्क बस परिवहन सेवा 5 से 20

किलोमीटर के दायरे में स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को दी जा रही है। प्रदेश में संचालित सीएम राईज स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास के लिये वर्ल्ड क्लास सेवायें दी जा रही है। भोपाल संभाग के 38 सीएम राईज स्कूल के 18 हजार 399, नर्मदापुरम् संभाग के 14 स्कूल के 5 हजार 130, उज्जैन संभाग के 39 स्कूल के 30 हजार 34, इंदौर संभाग के 28 स्कूल के 12 हजार 278 विद्यार्थियों को इस निःशुल्क बस परिवहन सेवा का लाभ दिया जा रहा है। सिंगरौली जिले के 4 स्कूलों के 2 हजार 876, कटनी के एक स्कूल के 732 और ग्वालियर जिले में डबरा के एक स्कूल के 475 विद्यार्थियों को निःशुल्क परिवहन सेवा का लाभ मिल रहा है। निःशुल्क परिवहन सेवा के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने संचालित बसों के लिये प्रायवेट बस ऑपरेटर्स से अनुबंध किया है। संचालित बसों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के लिये व्यापक इंतजाम भी किये गये हैं।

लोटन यात्रा

1000 शिकायतों का पुलिंदा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा फरियादी

सिर पर चप्पल रखकर कलेक्टर से कहा-अब तो न्याय दे दो

भोपाल। एक हजार शिकायतों का पुलिंदा लेकर लोटन करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस में पहुंचे इस शख्स का नाम मुकेश प्रजापति है। वह सिंगोली तहसील के गांव कांकरिया तलाई का रहने वाला है। भ्रष्टाचार के एक मामले में पिछले सात साल से शिकायत कर रहा है लेकिन हर बार कार्रवाई के नाम पर लिपापोती हो रही है। कोई सुनवाई नहीं होने पर उसने लोटन यात्रा का सहारा लिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद उसने सिर पर चप्पल रखा लिया और

कहा कि अब तो न्याय दे दो। पीड़ित मुकेश प्रजापति ने कहा कि वह करीब 7 साल से गांव कांकरिया तलाई में हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूर होकर वह सभी शिकायती आवेदन की फोटो कॉपी गले में पहनकर लोटन यात्रा करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। पीड़ित के पास करीब एक हजार से अधिक शिकायती आवेदन हैं। दरअसल, सैकड़ों शिकायत के बावजूद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मुकेश का आरोप है कि उसकी लगातार शिकायतों के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में प्रशासन का ध्यानकर्षण के लिए वह शिकायतों की माला पहनकर रेंगता हुआ, उनके दरवाजे तक पहुंचा, ताकि इस बार उसकी सुनवाई हो सके। प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ यूं तो अलग-अलग तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, नीमच जिले की जावद विधानसभा के ग्राम काकरिया तलाई से मुकेश प्रजापत नामक एक व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है।

बागेश्वर बाबा नहीं भूलते शेख मुबारक की मदद

दो मुसलमान जिनसे उनका गहरा रिश्ता,रखते हैं बड़ी अहमियत

भोपाल। बागेश्वर बाबा के नाम से पूरे देश में चर्चित कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर हिंदू और हिंदुत्व को लेकर अपने एजेंडे की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग उन पर इस्लाम और मुस्लिम विरोधी होने का भी आरोप लगाते हैं। हालांकि, ना सिर्फ बागेश्वर बाबा के दरबार में कई मुस्लिम भक्त भी आते हैं, बल्कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जीवन में दो मुस्लिम व्यक्तियों की काफी अहमियत है। शास्त्री अक्सर इनकी तारीफ करते दिखते हैं। आइए बताते हैं उन दो मुस्लिम व्यक्तियों के बारे में जिनकी धीरेंद्र शास्त्री से काफी करीबी है। दोनों से ही उनका नाता वर्षों पुराना है। इनमें से एक हैं धीरेंद्र शास्त्री के बचपन के दोस्त शेख मुबारक और दूसरे उनके शिक्षक अलीम खान। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से छह साल बड़े शेख मुबारक पेशे से एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं। उनकी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से गहरी दोस्ती है। धीरेंद्र से पीठाधीश्वर बनने के सफर में शेख मुबारक हर कदम उनके साथ रहे। दोनों के बीच दोस्ती इतनी पक्की कि समय मिलते ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शेख को अपने पास बुला लेते हैं या फिर खुद उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। शेख मुबारक बागेश्वर बाबा के साथ अपनी दोस्ती को लेकर एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। वह कहते हैं कि उनकी पहली मुलाकात अचानक गंज गांव के पास बारिश के दौरान हुई थी। पहली मुलाकात में दोनों का झगड़ा हो गया, लेकिन बाद में गहरी दोस्ती हो गई। शेख याद करते हैं कि शुरुआत में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की आर्थिक स्थिति ठीक नही थी, सभी दोस्त उनकी मदद करते थे।

जब शास्त्री ने अपनी बहन की शादी तय की तो सभी दोस्तों ने उनकी आर्थिक मदद की। उन्होंने भी तब करीब 20 हजार रुपए दिए थे। धीरेंद्र शास्त्री इसे आज तक नहीं भूले और कई बार मंचों से भी इसका जिक्र कर देते हैं। शेख मुबारक चुरारन गांव के रहने वाले है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री गढ़ा गांव के दोनों के गांव में काफी दूरी है। इसके बावजूद दोनों में पारिवारिक संबंध हैं। शेख कहते हैं कि त्योहारों पर एक दूसरे के घर आना-जाना होता है। अभी रक्षा बंधन पर उन्होंने भी शास्त्री की बहन से राखी बंधवाई थी। शेख मुबारक बताते है कि भले ही आज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि पूरी दुनिया में हो लेकिन वे इतने सरल है की समय मिलते ही मुझ से मिलने के लिए आ जाते है। कई बार रास्ते में जब मैं उन्हें नहीं देख पता हूं तो वो खुद अपना काफिला पीछे करवाते हैं और मुझ से मिलते हैं। उनकी दोस्ती आज भी पहले जैसे ही है कुछ भी नही बदला है। हलीम खान दूसरे ऐसे मुस्लिम व्यक्ति हैं जिनकी धीरेंद्र शास्त्री के जीवन में बड़ा महत्व है। हलीम खान धीरेंद्र शास्त्री के बचपन के शिक्षक हैं। गंज गांव के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल में वह धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को गणित पढ़ाते थे। दोनों के बीच काफी स्नेह था और गुरु शिष्य का यह रिश्ता आज भी पहले की तरह कायम है। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने स्कूल में पहुंचे तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करते दिखे थे।

शहर के साथ गांवों की सड़कें भी जर्जर, निकलना मुश्किल

भोपाल जिपं सदस्यों ने मंत्री को सौंपी खराब सड़कों की लिस्ट, जल्द सुधारने की मांग

भोपाल। बारिश की वजह से भोपाल की सड़कें जर्जर हो गई हैं। शहर के साथ गांवों की सड़कें भी खराब है। इसके चलते अब जनप्रतिनिधि आगे आए हैं और सड़कों के सुधार की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय मेहर ने पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को भोपाल की खराब सड़कों की लिस्ट

भी सौंपी है। जिन्हें जल्द ठीक कराने की मांग की है। भोपाल जिपं सदस्य मेहर ने बताया कि बैरसिया ब्लॉक की कई गांवों में सड़कों की हालत खस्ता है। इनके मरम्मत एवं डामरीकरण की मांग को लेकर मंत्री सिंह से उनके निवास पर जाकर खराब सड़कों की नाम की लिस्ट सौंपी। मंत्री सिंह को बताया कि बैरसिया ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं मजीरे टोल की कच्ची सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत स्वीकृत की जाए। साथ ही खराब सड़कों पर डामरीकरण हो। ताकि, ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी नहीं हो। अभी सड़कों पर चलना मुश्किल हैं। निदानपुर पंचायत की चौकी से निदानपुर टोला तक, चौकी से ग्राम खितवास तक, सोहाया जोड़ से पनिया गांव तक, कडैयाशाह से हिम्मतबाबा मंदिर मार्ग होते हुए ग्राम सलौई तक, रानी खजूरी से चक तक, सालाखेड़ी से बुगली तक, भूरी पड़ार से जमूसर तक, खितवास से जूना पानी तक, सलौई से उमरबाड़ी तक और चौकी से ग्राम गौंडीपुरा तक।

भोपाल में चल रही गड्ढों में 'कागज की नाव'

बता दें कि राजधानी के कई इलाकों में गड्ढों में सड़कें ढूंढना पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा निगम की सड़क खस्ताहाल है। नगर निगम की करीब 4 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। एमपी नगर, होशंगाबाद रोड, बांसखेड़ी, दानिशकुंज, बीडीए, अवधपुरी, दानिश चौराहा, मंदाकिनी समेत कई प्रमुख सड़कें ऐसी हैं, जहां से हर रोज लाखों लोग गुजरते हैं। बावजूद सड़कों की हालत नहीं सुधारी गई है। यही कारण है कि अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सोमवार को ऐशबाग इलाके में प्रदर्शन किया गया था। लोगों ने सड़क के गड्ढे में कागज की नाव भी चलाई थी। यही हाल गांवों की सड़कों के भी है।

स्वच्छ भारत मिशन में अधिक से अधिक जन-भागीदारी पर जोर

स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए हुई कार्यशाला,कई मुद्दों पर हुआ विचार

भोपाल। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 पर केन्द्रित करते हुए आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 की तैयारियों एवं उनके क्रियान्वयन के लिये विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने आपसी अनुभव को साझा किये। इन कार्यशालाओं के माध्यम से विभागीय अमले को नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वच्छ सर्वेक्षण, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, जल प्रबंधन आदि विषयों पर जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन के बेहतर क्रियान्वयन के लिये जनभागीदारी बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यशाला में 214 नगरीय निकायों के 447 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को भोपाल में स्थित कबाड़ से जुगाड़, एस.टी.पी. ट्रांसफर स्टेशन और प्र-संस्करण इकाइयों का अवलोकन कराया गया। प्रतिभागियों को बताया गया कि स्वच्छता कार्यक्रम को जन-आंदोलन का रूप दिया जाये। इसमें महिला-पुरूषों, युवाओं, छात्र-छात्राओं की जनभागीदारी भी सुनिश्चित की जाये।

विधानसभा की नवगठित समितियों की पहली बैठक सम्पन्न

विधायकों से नरेन्द्र तोमर बोले-मालद्वीप, स्विटजरलैंड घूमने के बजाय प्रदेश का दौरा करें

भोपाल। मप्र विधानसभा की समितियों की मंगलवार को पहली बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के साथ समितियों के सदस्य और सभापति मौजूद रहे। इस बैठक में संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते शामिल नहीं हुए। स्पीकर तोमर के साथ डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल, लोकलेखा समिति के सभापति भंवर सिंह शेखावत, विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह मौजूद रहे। समितियों की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा- आप सब लोग विभागीय दृष्टि से पूरे प्रदेश का दौरा भी कर सकते हैं। कई बार लोग मालद्वीव, स्विटजरलैंड दुनिया भर में घूमने जाते हैं। अपने मप्र में ही ओमकारेश्वर जाएं, उज्जैन महाकाल जाएं, दतिया की पीतांबरा माई के दर्शन करने जाएं। पहले अपने राज्य को ढंग से घूमें उसके बाद राज्य के बाहर जाएं। विदेश घूमने से अच्छा अपने प्रदेश का दौरा करें और देखें की सरकार की व्यवस्थाएं ठीक चल रहीं हैं या नहीं। दौरों का प्रतिवेदन बनाकर दें ताकि सरकार से अपेक्षित सुधार कराया जा सके। समितियों के सभापति और सदस्यों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि विधानसभा की समितियों का बड़ा महत्व है। जब सत्र नहीं चलता उस दौरान इन समितियों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कई समितियों के पास लंबे समय से बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। जैसे आश्वासन समिति के पास लंबे समय से मामले पेंडिंग हैं। सदस्यों को जो आश्वासन दिए गए उनपर क्या हुआ। इसको लेकर व्यापक चर्चा

इन समितियों की बैठक में होनी चाहिए।

इन समितियों में ये विधायक शामिलः लोक लेखा समिति- भंवर सिंह शेखावत इस समिति के सभापति हैं। जयंत मलैया, भूपेन्द्र सिंह, मीना सिंह, संजय पाठक, हरिशंकर खटीक, राजेन्द्र पांडेय, चंद्रशेखर देशमुख, रीति पाठक, हेमंत कटारे, रजनीश सिंह इसके सदस्य हैं। प्राक्कलन समिति- इस समिति में अजय बिश्नोई सभापति हैं। ओमप्रकाश धुर्वे, मालिनी गौड़, रामेश्वर शर्मा, आशीष गोविंद शर्मा, रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, अभय मिश्रा, दिनेश जैन बोसख संजय उइके इसके सदस्य हैं। सरकारी उपक्रमों संबंधित समिति- उषा ठाकुर इस समिति की सभापति हैं। इस समिति में सुरेंद्र पटवा, हरि सिंह रघुवंशी, सूर्य प्रकाश मीणा, प्रहलाद लोधी, डॉ. योगेश पंडाग्रे, राकेश शुक्ला (गोलू) फूल सिंह बरैया, हेमंत कटारे, विपिन जैन सदस्य हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में विसाहू लाल सिंह सभापति हैं। जय सिंह मरावी, डॉ प्रभु राम चौधरी, उमा देवी खटीक, पन्नालाल शाक्य, राजेंद्र मेश्राम, कालू सिंह ठाकुर, चंदर सिंह सिसोदिया, सुरेश राजे, राजन मंडलोई, हीरालाल अलावा इसके सदस्य हैं। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति- रमेश मेंदोला इस समिति के सभापति हैं। शैलेंद्र जैन, अशोक रोहाणी, विश्वामित्र पाठक, हेमंत खंडेलवाल, राजेश सोनकर, घनश्याम चंद्रवंशी, दिव्यराज सिंह, डॉ सतीश सिकरवार, जयवर्धन सिंह और सचिन यादव इसमें सदस्य हैं। पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति- इस समिति में महेंद्र हडिया सभापति हैं। दिनेश राय मुनमुन, मनोज चौधरी, हजारीलाल दांगी, संदीप जयसवाल, अरुण भीमाबाद, अमर सिंह यादव, मोहन सिंह राठौर, दिनेश गुर्जर, राजेंद्र भारती और सिद्धार्थ कुशवाहा इसके सदस्य हैं।

41 साल में पहली बार...गणेशोत्सव में एआई का बोलबाला

पंडाल से लेकर मूर्तियों के डिजाइन तक,हर ओर हो रहा इस्तेमाल

भोपाल। गणेश चतुर्थी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में उत्साह है। कई प्रमुख गणेश पंडालों के आयोजकों ने आगामी उत्सव के लिए पंडालों और मूर्तियों के जटिल सेटों को डिजाइन करने के लिए एआई की मदद ली है। काशी, अमरनाथ मंदिर और कई मंदिरों के एआई-निर्मित पवित्र घाट भगवान गणेश की विशेषता वाले लुभावने चश्मे फिलहाल निर्माण के अंतिम चरण में हैं, जिन्हें इस त्योहारी सीजन के दौरान पंडालों में शानदार ढंग से प्रदर्शित किया जाएगा। पंडाल का डिजाइन एआई की क्षमताओं का उपयोग करके सरलता से तैयार किया गया है और तैयारी पहले से ही पूरी हो चुकी है। यह 41 साल के इतिहास में पहला उदाहरण है कि पंडाल डिजाइन की संकल्पना एआई का उपयोग करके की गई है, क्योंकि यह नया नजरिया एडवांस डिजाइनिंग की सुविधा प्रदान करेगा। सार्वजनिक महोत्सव समिति सचिव अनिल आगा ने कहा कि जयरामपुर कॉलोनी का गणेशोत्सव 7 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। 11 दिवसीय उत्सव के दौरान, संगीतमय आरती, भावपूर्ण भजन संध्या, पवित्र प्रसाद का वितरण और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न सामाजिक पहल भी की जाएंगी। बड़े पैमाने पर गणेशोत्सव से जुड़े कई आयोजकों ने इस साल अपने

पंडालों को डिजाइन करने के लिए एआई की मदद ली है। इंदौर के गोयल नगर के रहने वाले तीसरी पीढ़ी के मूर्ति निर्माता अतुल पाल ने कहा, मैंने कस्टमर्स की जरुरतों को वास्तविकता में बदलने के लिए ऑनलाइन डिज़ाइन बनाई और एआई का लाभ उठाया। टेक्नोलॉजी ने वास्तव में हमारे विचारों और क्रिएटिविटी को पंख दिए हैं। इस वर्ष, मैं भक्तों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न आकारों की 1000 गणेश मूर्तियां तैयार कर रहा हूं। मौसम विभाग द्वारा बारिश के पूर्वानुमान के आलोक में, अधिकांश पंडालों का निर्माण वाटरप्रूफ बनाया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि वह भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना कर सकें। मालवा कला अकादमी ने अपने पंडाल को पवित्र अमरनाथ मंदिर की नकल से डिजाइन किया है, जहां 31 फुट ऊंची भव्य गणेश प्रतिमा श्रद्धापूर्वक स्थापित की जाएगी। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। मालवा कला अकादमी के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि हम इस साल भी गर्व से 31 फुट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। यह सेटअप अमरनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, जिसे पश्चिम बंगाल के 30 से अधिक कुशल कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है। पंडाल और मूर्ति सेटअप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंदौर को पश्चिम बंगाल के प्रतिभाशाली कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है, जो इस पवित्र कला के प्रति अपने असाधारण कौशल और समर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं।

संपादकीय

देर रात सड़कों पर गाड़ियां नहीं यमदूत चल रहे हैं

महानगरों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वे हर आदमी को ठिकाना मयस्सर नहीं करा पाते। वहां लोगों को गुजारे का कोई जरिया भले मिल जाए, पर हर किसी को सिर पर छत नसीब नहीं हो पाती। लाखों लोग दिन भर दिहाड़ी करके, रिक्शा-रेहड़ी-ठेला खींच कर या भीख मांग कर किसी तरह गुजारे भर की आमद तो कर लेते हैं, पर रात गुजारने के लिए उन्हें फुटपाथों पर खुले आसमान या उपरिगामी पुलों के नीचे, खाली बंद दुकानों के बाहर कोई जगह तलाशनी पड़ती है। इस तरह इन्हें मौसम की मार तो झेलनी ही पड़ती है, अक्सर तेज रफ्तार वाहनों के नीचे आकर दम तोड़ देने या अपंग होने का खतरा भी बना रहता है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर एक बेकाबू ट्रक के चढ़ जाने की घटना इसकी ताजा कड़ी है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो को गंभीर स्थिति में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे हादसों की खबरें कुछ-कुछ समय पर हर महानगर से मिल जाती हैं। हर घटना के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस तरह सड़कों के किनारे, फुटपाथों पर सोने वालों के लिए कोई सुरक्षित इंतजाम क्यों नहीं किया जाता। हालांकि अनियंत्रित वाहनों के सड़कों के बीच की जगहों और फुटपाथों पर चढ़ने से रोकने की गरज से बहुत सारी जगहों पर लोहे की मजबूत बाड़ लगाई जाती है, मगर बहुत सारी जगहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि शहरों में सड़कों पर रात में भी आवाजाही लगी रहती है। रात के वक्त शहरों की सड़कें खासकर माल ढुलाई वाले वाहनों के लिए खोल दी जाती हैं। इसके अलावा, बहुत सारे युवा देर रात को शराब पीकर वाहन दौड़ाना अपनी शान समझते हैं। वाहनों के अनियंत्रित होकर फुटपाथों पर चढ़ जाने की घटनाएं अक्सर शराब के नशे में गाड़ी चलाने की वजह से होती पाई गई हैं। हालांकि दिल्ली में जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है, इसके बावजूद बहुत सारे वाहन चालकों की मनमानी पर लगाम लगाना कठिन बना हुआ है। देर रात को उनकी मनमानी और बढ़ जाती है। इससे यातायात व्यवस्था पर तो प्रश्नचिह्न लगता ही है, रोजी-रोजगार की तलाश में हर वर्ष लाखों की संख्या में आने वाले लोगों के लिए रहने की व्यवस्था पर भी गंभीरता से विचार की जरूरत रेखांकित होती है। अनेक मौकों पर यह बात कही जाती रही है कि बढ़ते पलायन और महानगरों पर उसके बढ़ते बोझ की वजह से सरकारों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना चुनौती है।

इसके समाधान की दिशा में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मगर न तो सरकारों ने रोजी-रोजगार के साधनों के विकेंद्रीकरण पर गंभीरता से विचार किया, न महानगरों में सबके रहने के ठिकाने उपलब्ध कराने की व्यावहारिक पहल हो पाई। दिल्ली में रैन बसरे बनाए तो गए, मगर उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि लोगों को फुटपाथों पर सोने को मजबूर न होना पड़े। उनमें भी जरूरी सुविधाओं के अभाव की शिकायतें आती रहती हैं। दरअसल, महानगरों में बेआसरा लोगों के बारे में कोई व्यावहारिक नीति बनाने के बारे में सोचा ही नहीं गया। अगर जगह-जगह, थोड़े शुल्क के साथ भी, धर्मशाला जैसी रात गुजारने की जगहें बना दी जाएं, तो लोगों के जिंदगी जोखिम में डाल कर फुटपाथ पर सोने से काफी हद तक निजात दिलाई जा सकती है।

नजरिया

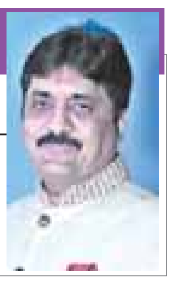

ललित गर्ग

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सर्वसुलभ इंसाफ की उम्मीद को पंख लगे

यह सुखद, अविस्मरणीय एवं ऐतिहासिक अवसर ही है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 75 साल का गरिमामय सफर पूरा कर लिया है। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के प्रयासों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को यादगार बनाने के लिये बाकायदा डाक टिकट व सिक्के भी हाल ही में जारी किये गए और विभिन्न आयोजनों में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को अधिक सशक्त बनाने के विषय पर गंभीर मंथन भी हुआ, ऐसे ही आयोजनों में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड ने इस बात पर बल दिया कि समय पर न्याय मिलने से ही न्याय का वास्तविक लक्ष्य पूरा होता है। 'न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है' वाली इस बात को सभी महसूस करते हैं लेकिन न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर आसीन मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की इस स्वीकारोक्ति के गहरे निहितार्थ हैं। 'न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है।'

सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती के अवसर पर सभी ने शीघ्र न्याय की जरूरत को स्वीकारते हुए कहा कि 'तारीख पे तारीख' की संस्कृति से तौबा करने का वक्त आ गया है? न्याय प्रणाली की कमियों को दूर करने के रास्ते उद्घाटित होने ही चाहिए। यही वजह है कि जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कुछ कहा, उसे देश की पूरी न्याय व्यवस्था के लिए अलार्म बेल माना जा सकता है। राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि जब तक न्यायपालिका देश के आम लोगों को सहजता से इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता मुहैया नहीं कराती, तब तक उसका काम पूरा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिये अदालतों में स्थगन की संस्कृति को बदलने के प्रयास करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने स्वीकारा कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का होना हम सभी के लिये बड़ी चुनौती है।

अदालतों से न्याय पाने की प्रक्रिया बड़ी खर्चीली है और इसमें बेहिसाब वक्त लगता है। इन दोनों ही का नतीजा इसी रूप में सामने आता है कि इंसाफ की आस लेकर अदालत पहुंचा व्यक्ति फैसला आने तक टूट चुका होता है। इसीलिये राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा कि किसी गंभीर अपराध से जुड़े मामले का फैसला आने में 32 साल लग जाए तो लोगों को ऐसा लगना अस्वाभाविक नहीं कि शायद अदालतें ऐसे मामलों को लेकर संवेदनशील नहीं हैं। राष्ट्रपति ने किसी खास मामले का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका इशारा अजमेर में पॉक्सो अदालत द्वारा इसी 20 अगस्त को सुनाए गए फैसले की तरफ था। एक चर्चित सेक्स स्कैंडल से जुड़े इस मामले में छह लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाने में 32 साल लग गए। यह अपनी तरह का कोई इकलौता मामला नहीं है। बेहद गंभीर और वीभत्स अपराध के सैकड़ों ऐसे मामले हैं, जो अदालतों में बरसों से लंबित पड़े हैं। लोग अदालतों में मुकदमों के लंबे खिंचने से इतने त्रस्त हो जाते हैं कि किसी तरह समझौता करके पिंड छुड़ाना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयन्ती पर महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि न्यायपालिका और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या करने जा रहा है, जिससे लोग न्याय प्रक्रिया से हताश-निराश होकर समझौता करने के लिए बाध्य न हों? प्रश्न यह भी है उन्हें समय पर त्वरित न्याय कब मिल सकेगा? दुर्भाग्य से ये प्रश्न दशकों से अनुत्तरित है।

इससे पहले जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ सके। निस्संदेह, हाल के वर्षों में महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे हमारे समाजशास्त्री और कानून लागू करवाने वाली विभिन्न एजेंसियां भी हैरान-परेशान हैं। कोलकाता में एक मेडिकल कालेज के अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या कांड ने पूरे देश को उद्वेलित किया है। पूरे देश में अपराधियों को शीघ्र व सख्त दंड देने की मांग की जा रही है। यदि पुलिस व जांच एजेंसियां पुख्ता सबूतों के साथ अदालत में पहुंचें तो गंभीर मामलों में आरोप जल्दी सिद्ध हो सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है। ये यात्रा है भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की। ये यात्रा है एक लोकतंत्र के रूप में भारत के और परिपक्व होने की। भारत के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी न्यायपालिका पर विश्वास किया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ये 75 वर्ष 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' के रूप में भारत के गौरव को और बढ़ाते हैं। आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है विकसित भारत, नया भारत बनने का। नया भारत, यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत। हमारी न्यायपालिका इस विजन का एक मजबूत स्तम्भ है। भारत में लोकतंत्र और उदारवादी मूल्यों को मज़बूत करने में न्यायपालिका ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संविधान का रखवाला, ग़रीबों के अधिकार एवं सरकार की ज्यादतियों के खिलाफ़ कमज़ोर समूहों का योग्य संरक्षक और करोड़ों नागरिकों के लिए आखरी उम्मीद वाला संस्थान है सुप्रीम कोर्ट। कुछ अपवादों को छोड़कर पिछले 75 वर्षों में ज्यादातर समय भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा और क़ानून के शासन को बनाए रखने में सफल रही है। लेकिन भारतीय कानून व्यवस्था के सामने अनेक जटिल स्थितियां भी हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति, बढ़ते केसों की संख्या, जवाबदेही, भ्रष्टाचार एवं विलम्बित न्याय आदि। न्याय को लेकर अदालतों तक आम नागरिकों की पहुंच एवं खर्च के मुद्दों और इसी तरह की दूसरी चीज़ों के मामले में सुधार के बारे में न्यायपालिका की अपनी महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। हमारे कानूनों की भावना है-नागरिक पहले, सम्मान पहले और न्याय पहले है।

निश्चित ही डी.वाई. चंद्रचूड न्याय-प्रक्रिया की कमियों एवं मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं तो उनमें सुधार के लिये जागरूक दिखाई दिये हैं। निश्चित ही उनसे न्यायपालिका में छाये अंधेरे सायों में सुधार रूपी उम्मीद की किरणें दिखाई देती रही है। न्याय के इंतजार में कई-कई पीढ़ियां अदालतों के चक्कर काटती रह जाती हैं। देश में शीर्ष अदालत, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में मुकदमों का अंबार निश्चित रूप से न्यायिक व्यवस्था के लिये असहज एवं चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगभग 80 हजार है। उच्च न्यायालयों में इनकी संख्या 62 लाख के करीब है और निचली अदालतों में करीब साढ़े चार करोड़। इसका अर्थ है कि लगभग पांच करोड़ लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं। देश में तीनों स्तरों पर लंबित मामले न्यायिक व्यवस्था के लिये एक गंभीर चुनौती है। आजादी के अमृत महोत्सव की चौखट पार कर चुके देश की इस त्रासद न्याय व्यवस्था के बाबत देश के नीति-नियंताओं को गंभीरता से विचार करना चाहिए। निश्चित ही भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के अनुपात में पर्याप्त न्यायाधीशों व न्यायालयों की उपलब्धता नहीं है।

निचली अदालतों से लेकर शीर्ष अदालत तक किसी भी मामले के निपटारे के लिए नियत अवधि और अधिकतम तारीखों की संख्या तय होनी ही चाहिए। जैसाकि अमेरिका में किसी भी मामले के लिये तीन वर्ष की अवधि निश्चित है। लेकिन भारत में मामले 20-30 साल चलना साधारण बात है। तकनीक का प्रयोग बढ़ाने और पुलिस द्वारा की जाने वाली विवेचना में भी सुधार जरूरी है। उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देशों की तरह भारत की एक अत्यंत शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका है। तारीख पर तारीख का सिलसिला थम सके इसके लिये हाल ही में लागू हुए तीन नये आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद स्थिति में सुधार की उम्मीद जगी है। नये तीन कानूनों के बाद मुकदमों की सुनवाई द्रुत गति से होगी, लेकिन देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं? प्रश्न यह भी है कि आखिर करोड़ों लंबित मामलों का क्या होगा? ये वे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर देश की जनता को चाहिए। न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिये।

राजनीति

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

हिमंत बिस्वा सरमा के वक्तव्य पर राजनीति के मायने

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के 'मियां मुस्लिम' संबंधी बयान पर इन दिनों एक विशेष वर्ग की ओर से जमकर राजनीति हो रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद एवं वे तमाम संगठन इस वर्ग विशेष के अगुआ हैं जोकि मुस्लिम हितों की गारंटी ही नहीं लेते बल्कि सरकार एवं अन्य समाजों के बीच अपनी आवाज यह कहकर बुलंद करते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनका यह आरोप आम है कि हुकूमत उन पर बहुत जुल्म कर रही है। अब यह अलग बात है कि केंद्र की मोदी सरकार या इससे पहले की कांग्रेस जवाहर लाल नेहरु से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक या अन्य सरकारें वह फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा, इंद्रकुमार गुज़राल, अटल बिहारी वाजपेयी की ही क्यों न रहीं हों, जिनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में लगातार अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक लाभ मुसलमानों को दिया गया और उन्होंने बहुत सफलता से उसे उठाया भी है। फिर भी हुकूमत से शिकायत इस वर्ग में अधिकांश लोगों की आम है।

दूसरी ओर राज्यों के स्तर पर भी अब तक जितनी भी राज्य सरकारें हुईं, जिसमें असम भी शामिल है और आज के वहां जो मुख्यमंत्री हैं, वे हिमंत बिस्वा सरमा भी। उन सभी प्रदेशों और इनके मुख्यमंत्रियों ने शासन स्तर पर योजनाओं के लाभ और संवैधानिक नियमों के अनुसार अल्पसंख्यकों को मिलने वाले हितों में कोई कमी मुसलमानों के लिए कभी नहीं रखी है, जिसमें कि आज भारत सरकार एवं राज्य सरकार के पास मुसलमानों को मिले लाभ के आंकड़े भी मौजूद हैं। इसके बाद भी भारत की ये इस्लामिक संस्था 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद' और इन जैसी अन्य इस्लामी संस्थाएं हैं कि इन्हें हर उस सरकार से शिकायत है, विशेषकर उससे जोकि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है।

कहना होगा कि हिमंत बिस्वा सरमा के इस 'मियां मुस्लिम' बयान को लेकर व्यर्थ ही 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद' टार्गेट कर रही है, जबकि वह जानती है कि मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा का ये वक्तव्य भारत के मुसलमान नागरिकों के लिए नहीं है, जो कहा जा रहा है वह बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए है। फिर भी उसे इस शब्द के बोलने पर आपत्ति है। सोचने वाली बात है कि ये बुरा जमीयत को इस हद तक लग गया कि उसने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने तक का आग्रह कर डाला ! आश्चर्य यह भी है कि जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी सीजेआई तक ही नहीं रुकते। वह गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर असम के मुख्यमंत्री पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जमीयत चीफ ने मुख्यमंत्री हिमंत के बयान को संपूर्ण भारत के मुसलमानों से भी जोड़ दिया है । कह रहे हैं, 'असम के मुख्यमंत्री का दिया यह बयान संपूर्ण भारत के मुसलमानों को एक विशेष नजरिए से देखता है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मियां बुलाकर सीएम ने उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा देने की कोशिश की है।'

अब जरा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का पक्ष भी जान लेना चाहिए; असम कैबिनेट ने कुछ समय पहले ही राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी । साल 2022 में पांच मुस्लिम वर्गों की पहचान करके उन्हें स्वदेशी असमिया मुसलमानों के रूप में मान्यता दी गई। ये सभी असमिया भाषा बोलने वाले लोग हैं। किंतु दूसरा एक और समुदाय है, जिसे असम में मियां मुसलमान कहा गया है और ये लोग बांग्ला भाषी हैं और उनमें जो संख्या बांग्लादेश से आकर यहां बस गई है, उस जनसंख्या का अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक बताया जाता है। इसलिए इस मुस्लिम आबादी को लेकर अक्सर यहां विवाद होता है। यहां हिमंत बिस्वा सरकार एक फिल्टर लगाने की बात करती है ताकि बाहरी मुस्लिमों को पहचान करना आसान हो और उन्हें बाहर किया जा सके।

हिमंत बिस्वा कहते हैं, 'मैं असम को 'मियां भूमि' नहीं बनने दूंगा। असम के जनसांख्यिकी को परिवर्तित करने और स्थानीय लोगों को अल्पसंख्यक में लाने के लिए एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अतिक्रमण चल रहा है। यह केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्वर्गीय गोपीनाथ बोरदोलोई, विष्णु राम मेधी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है।' यहां समझनेवाली बात यह भी है कि असम को छोड़कर सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह कानून है कि गैर-स्थानीय लोग भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते। चूंकि असम में ऐसा कानून नहीं है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बसने के लिए विकल्प के तौर पर इस राज्य को चुना है, जिससे उन्हें भूमि व अन्य संबंधित अधिकार जैसे-सरकारी सहायता, रोजगार, चिकित्सा-लाभ आदि प्राप्त करने में आसान मदद मिलती है ।

कहना होगा कि यह मुस्लिम जनसंख्या का आंकड़ा अचानक नहीं है। यह उनकी जन्म दर के संख्यात्मक विस्फोट का परिणाम है। बांग्लादेश से घुसपैठ नहीं रुक पाने के कारण से ही यह बार-बार कहा जा रहा है कि असम का 20 वर्ष में मुस्लिमीकरण हो जाएगा। अभी नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर भी सभी ने देखा कि कैसे इसे विवाद का विषय इस्लामवादियों ने पूरे देश में बना दिया था। इसके माध्यम से पूरे विश्व को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार असम में मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। यहां पूरे असम को आग के हवाले करने में कोई हिचक इन इस्लामवादियों में नहीं थी। जबकि इससे जुड़ी हकीकत यह है कि इसे 1951 में असम के सभी निवासियों के लिए 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लागू किया गया था। उद्देश्य भी साफ था कि 25 मार्च, 1971 के पहले से जो राज्य में रह रहे हैं, उन लोगों या उनके पूर्वजों की पहचान की जाएगी, और उस आधार पर जिन्हें 1951 का नागरिक पाया जाएगा, वे अद्यतन एनआरसी में शामिल हो जाएंगे । पूरा एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में किया गया था, किंतु इसके बाद भी व्यापक तौर पर एक बड़ी संख्या जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, अपना नाम इसमें डलवाने में कामयाब हो गए। यहां फर्जी पहचान के आधार पर कई बांग्लादेशियों ने भूमि-भवन, सरकारी लाभ भी प्राप्त कर लिए हैं । यही कारण है कि भाषायी तौर पर इनकी असली पहचान कर इन्हें राज्य से बाहर करना आज बहुत कठिन हो गया है ।

इस सब के बीच हमें यह जरूर याद रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2015 में उपमन्यु हजारिका आयोग गठित किया गया था, इस आयोग ने बांग्लादेश के साथ सटी सीमा की स्थिति पर अदालत को अपनी अहम चार रिपोर्ट सौंपी थीं। इसमें घुसपैठ रोकने का एकमात्र उपाय यही बताया गया था कि असम में कानून बनाकर भूमि, रोजगार, व्यापार आदि सिर्फ उनके लिए आरक्षित किया जाए, जिनके नाम या जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के एनआरसी में मौजूद हैं, वे असम के निवासी माने जाएं और अन्य को इससे बाहर कर दिया जाए । इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को प्रमुख बनाते हुए एक समिति बनाई थी, उसने भी 2020 में वही सुझाव दिए जोकि पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी दे चुकी थी। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भूमि, रोजगार, व्यापार के अधिकारों की रक्षा करने वाला कानून केवल उनके लिए हो, जिनके नाम 1951 एनआरसी में हैं।

अब इस पूरे मामले की समीक्षा करने के बाद आप वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कार्यों को देखिए; वह क्या कर रहे हैं? वह बता रहे हैं कि असम में 'मिंया मुसलमानों' की घुसपैठ के कारण से ही मूल असमियां लोगों के अस्तित्व पर संकट आया है। यदि ठोस उपाय नहीं किए गए तो 2040 तक असम की स्थानीय आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इसलिए वे (मुख्यमंत्री) उन सारे प्रयासों को कर रहे हैं, जिनसे कि स्थानीय लोगों का संरक्षण हो सके। ऐसे में जमीयत उलेमा-ए-हिंद का इस 'मियां मुसलमान' शब्द को बड़ा मुद्दा बनाने का कोई औचित्य समझ नहीं आता है। वास्वत में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा असम में आज वही कर रहे हैं जोकि इस राज्य के अस्तित्व एवं यहां के (मूल) स्थानीय निवासियों के संरक्षण के लिए अति आवश्यक है और इस राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें करना चाहिए ।

साहित्य में लेटरल इंट्री

डॉ. प्रदीप मिश्र

साहित्य में कुछ कर गुजरने की तमन्ना जोर मार रही थी। लेकिन मुश्किल यह थी कि साहित्य के सम्मान-सागर में घुसने के लिए, लंबी लाईन थी। लाईन में आगे आ पाना असंभव सा था। इससे हटने वाले कम और लगने वाले ज्यादा थे। दर्जन-भर सम्मान पा चुके। पाठ्य पुस्तकों में जगह मिल चुकी। पत्र-पत्रिकाओं में निर्बाध छपने लगे,लेकिन लाईन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कुछ तो मरने के बाद भी बतौर प्रेत,लाईन में लगे हैं। मरणोपरांत सम्मान ग्रहण करने से भी इन्हें परहेज नहीं है। वसीयत में लिखकर मरे थे कि,'मेरे लिए सबसे ज्यादा सम्मानों का जुगाड़ करने वाले पुत्र के नाम ही, मेरी जायजात की जाए।'

सो पुत्रगण पूरी ताकत से उन्हें सम्मान दिलाने में लगे हैं। उनके द्वारा खाली की गई जगह में अब उनके बेटे खड़े हैं। एक सम्मान के जुगाड़ में जाता है तो जगह घेरने के लिए दूसरा लाईन में लग जाता है। सम्मान लेकर आने के बाद वह लाईन में लगता है और दूसरा किसी दूसरे सम्मान के जुगाड़ में निकल जाता है। बड़े की पत्नी ने कहती है, 'हमने जिला- स्तर के दो सम्मान पिताजी को दिलावा दिए हैं । छोटे अभी एक ही दिलवा पाया है, वह भी तहसील-स्तर का। अब तो प्रापर्टी हमारे नाम हो जानी चाहिए।'

'ऐसे कैसे हो जानी चाहिए? हम लोग लगे हैं प्रदेश स्तर के सम्मान के लिए। घोषणा होने दो, पहले नंबर पर बुढ़उ का ही नाम होगा।' छोटे की पत्नी बोली।

साहित्य में सम्मानों की लाईन, कोई नहीं छोड़ रहा है। लोग सालों से लगे हैं। एक-एक रचना छपवाने में सारी साहित्यिक-ताकत झोंके दे रहे हैं। किताबें, खुद लिखते हैं, खुद छपवाते हैं और सप्रेम भेंट लिखकर, कूड़ेदान की शोभा बढ़ाने के लिए, किसी माननीय को सौंप आते हैं।

मैंने लाईन में,पार्श्वी से प्रवेश का जुगाड़ जमा लिया है। मैं नेताजी का चाटुकारिता-प्रमुख बन गया हूँ। उनकी प्रशस्ति ही अब मेरे साहित्यिक योगदानों का आधार है। बस इसीलिए अब मुझे साहित्यक सम्मान-सागर की लाईन में पार्श्व से प्रवेश यानी लेटरल इंट्री मिल चुकी है। लाईन में लगे-लगे बूढ़े हो जाने वाले लेखक, अब मुझसे काफी पीछे हो गए हैं।

लेटरल-इंट्री मिलते ही मैं अचानक से, एक महान् साहित्यकार बन गया हूँ।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

नंदकिशोर बर्वे

लेखक व्यंग्यकार हैं।

बिल्ली का भाग्य और सींके का बार-बार न टूटना

बिल्ली यदि इतनी ही भाग्यवान होती तो, वह मौसी क्यों बनती? भतीजा ही नहीं बन कर ही पैदा नहीं होती ! नहीं समझे ? अरे यार बिल्ली को मौसी कहते हैं ना, बस इसीलिए. अब देखिये उसका हाव भाव उठना बैठना, चलन फिरना सभी कुछ तो शेर जैसा होता है ना इसलिए शेर की मौसी कही जाती है . तो मुद्दे की बात यह है कि वह भाग्यवान नहीं होती है . बात वही है कि अगर इतनी ही मुकद्दर की सिकन्दर होती तो शेर बन कर ही पैदा ही होती.

अब चूँकि वह भाग्यवान नहीं है, तो उसके भाग्य इतने प्रबल कैसे हो सकते हैं ? कि ऊपर टंगा सींका उसके चाहने से या कि उसके कहने से टूटकर गिर पड़े . सींका कोई दलबदलू है , जो कहीं भी और कभी भी गिर पड़े ! तो बिल्ली भले ही उसके टूटने की उम्मीद में उम्मीद पाले बैठी रहे. लेकिन सींके को नहीं टूटना है , तो वह नहीं टूटता है . अब चाहने वालों का क्या है ? कोई कुछ भी चाह सकता है . किसी को भी चाह सकता है . इस चाहने पर तो किसी का कोई प्रतिबंध है नहीं . बात तो तब बने जब सामने वाल भी उसी शिद्दत से चाहे . पर ऐसा प्रायः होता नहीं है इसीलिए तो 'तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं' टाइप गाने बनते रहते हैं . सींके के नीचे बैठकर उसको टुकुर टुकुर सींके को देखकर ललचाना बिल्ली के भाग्य में लिखा होता है .तो वह वही कर सकती है . हाँ सींके तक पहुँचने की कूद फांद में अपने हाथ (?!) पैर अलग तोड़ बैठती है .इस तरह के भाग्य भरोसे सींके के टूटने के इंतज़ार में बैठी बिल्लियाँ हमरे समाज के हर तबके वर्ग , क्षेत्र में मौजूद होती हैं.

अब देखिये एक साधारण से दिखने वाले आदमी की पत्नी यदि सुन्दर हो तो लोगों की जुबान पर दो ही बातें आती हैं . या तो बिल्ली के भाग्य से सींके के टूटने की ,या फिर कौवे के मुंह में जलेबी की. अब जिसके भाग्य से सींका टूट गया तो टूट गया . उसको आनंद लेने दो . साहित्यकार नुमा वे लोग जो लिखने पढ़ने का काम कम और पुरस्कार / सम्मान पाने के जुगाड़ का काम अधिक करते हैं, वे भी भाग्यवान बिल्ली ही तो होते हैं . कि नहीं ? यूँ भी आजकल इस क्षेत्र में पुरस्कार सम्मान/ हड़पने वालों का औसत कुछ अधिक ही हो चला है . उस पर से व्यवहार भी शादी में दिए जाने वाले लिफाफे जैसा . तुम्हारे लिफाफे के वजन के अनुपात में मेरे लिफाफे का वजन. तुम मेरी प्रशंसा करो मैं तुम्हारी . जस्ट गिव एंड टेक !

तो मूल बात बिल्ली और सींके की है. पर एक बात तो है कि अगर बिल्ली सींका बांधने वाले से गठबंधन कर ले तो बात बनते देर नहीं लगेगी . यह एक और भी अलहदा बात है कि कई गठबंधन तमाम माथा फोड़ी के बाद भी सींके तक नहीं पहुंचते पाते हैं . इसीलिए आजकल गठबंधन को ठग बंधन भी कहा जाने लगा है . सींका बांधने वाला यदि बिल्ली से जा मिले और सींके को बिल्ली की सुविधानुसार बांध दे तो फिर बिल्ली को मुक़्दर का सिकंदर बनने में कितनी देर लगेगी.

इसलिए जो लोग स्वयं के बलबूते पर सींके तक नहीं पहुँच पाते हैं, वे सींका बांधने वाले तक पहुँचने की कोशिश करते हैं . इस जुगत में यदि सींका टूटकर सामने गिर पड़े तो मलाई मारने से कौन रोक सकता है? फिर मलाई चाहे दूध की हो या कि सत्ता की .

हमारी राजनैतिक व्यवस्था में ऐसी बिल्लियों की कोई कमी नहीं है , जो सींका बांधने वाले तक पहुँच बनाने की कोशिश में दिन रात एक किये दे रही हैं . पर इंतज़ार है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा. अब सत्ता रूपी सींके का इंतज़ार कोई चुपचाप बैठकर करेगा नहीं. उसके लिए जो उछल कूद करनी होती है वह तो करनी भी चाहिए. और करते हुए दिखाई देनी भी चाहिए . क्योंकि ज़माना - जो है, उससे अधिक दिखाने का है .

जब तक सत्ता की मलाई का सींका नहीं टूटता, तब तक प्रतिपक्ष के रूप में उपलब्ध सींकों के सामान से काम चलाना होता है . जैसे सामिष भोजी मनोनुकूल आहार न मिलने पर निरामिष भोजन से अपना समय काटता है . ऐसे समय में एक एक दिन एक एक युग जैसा बीतता प्रतीत होता है . और अपना प्रतिद्वंद्वी सत्ताधारी फूटी आँख नहीं सुहाता .अब किसी को कोई न सुहाए , तो न सुहाए . लोकतंत्र में जनता जनार्दन का फैसला ही सर्वोपरि होता है. उसका सम्मान किया जाना चाहिए . यह सभी समझें तो बेहतर .

पैरालंपिक खेल 2024

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

25 पदकों के अपने लक्ष्य को हासिल करेगा भारत!

पैरालंपिक खेलों का इतिहास काफी दिलचस्प है। पैरालंपिक का अर्थ है ओलंपिक के समानांतर खेल, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार दोनों आंदोलन एक साथ मौजूद हैं। माना जाता है कि इस तरह के खेलों की बुनियाद वर्ष 1948 में ब्रिटेन में उस समय रखी गई थी, जब द्वितीय विश्वयुद्ध में अनेक सैनिक बुरी तरह घायल हुए थे और उनमें से कई को अपने शरीर के विभिन्न अंग भी गंवाने पड़े थे। खासतौर से रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित ऐसे ही मरीजों के पुनर्वास के लिए तब सर लुडविग गुटमैन नामक एक विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट ने अलग-अलग अस्पताल के साथ इस प्रकार के खेलों का आयोजन शुरू किया था। इसीलिए उन्हें ही पैरालंपिक खेलों और संपूर्ण पैरालंपिक आंदोलन की स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का श्रेय दिया जाता है।

2024 के पैरालंपिक खेल इस समय पेरिस में चल रहे हैं, जिनका आयोजन प्रत्येक चार वर्ष में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों के कुछ ही दिनों बाद होता है। टोक्यो पैरालंपिक-2020 का आयोजन कोविड-19 के कारण 2020 के बजाय 2021 में हुआ था और उन खेलों में कुल 162 देशों ने हिस्सा लिया था। पैरालंपिक खेलों में इस बार कुल 549 पदक स्पर्धाओं में 184 देशों के करीब 4400 एथलीट 22 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें भारत के भी 84 खिलाड़ी 12 खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। भारतीय पैरा-एथलीट इस बार के पैरालंपिक खेलों में अपने अदम्य हौंसले और इच्छाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 अगस्त को पेरिस पैरालंपिक में भारत ने केवल दो घंटे में ही चार पदक (निशानेबाजी में तीन और ट्रैक इवेंट में एक) जीतकर इतिहास रच दिया था, जिनमें अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक, मनीष नरवाल ने रजत और मोना अग्रवाल तथा प्रीति पाल ने कांस्य जीता। यह लेख लिखे जाने तक भारत पैरालंपिक में 3 स्वर्ण और 5 रजत सहित कुल 15 पदक जीत चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि भारत इस बार कम से कम 25 पदक जीतकर एक नया इतिहास रचने में सफल हो सकता है।

वैसे पैरालंपिक खेलों का इतिहास काफी दिलचस्प है। पैरालंपिक का अर्थ है ओलंपिक के समानांतर खेल, जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार दोनों आंदोलन एक साथ मौजूद हैं। माना जाता है कि इस तरह के खेलों की बुनियाद वर्ष 1948 में ब्रिटेन में उस समय रखी गई थी, जब द्वितीय विश्वयुद्ध में अनेक सैनिक बुरी तरह घायल हुए थे और उनमें से कई को अपने शरीर के विभिन्न अंग भी गंवाने पड़े थे। खासतौर से रीढ़ की हड्डी की चोटों से पीड़ित ऐसे ही मरीजों के पुनर्वास के लिए तब सर लुडविग गुटमैन नामक एक विख्यात न्यूरोलॉजिस्ट ने अलग-अलग अस्पताल के साथ इस प्रकार के खेलों का आयोजन शुरू किया था। इसीलिए उन्हें ही पैरालंपिक खेलों और संपूर्ण पैरालंपिक आंदोलन की स्थापना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का श्रेय दिया जाता है।

सर गुटमैन जर्मनी में द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले के प्रमुख न्यूरोलॉजिस्टों में से एक थे, जो ब्रेस्लाउ में यहूदी अस्पताल में काम करते थे लेकिन 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध शुरू होने पर उन्हें इंग्लैंड भागने पर मजबूर होना पड़ा था। विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद 1944 में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर उन्होंने युद्ध में हताहत हुए और रीढ़ की हड्डी की चोटों से जूझ रहे ब्रिटिशों को मेडिकल सेवाएं मुहैया करने के लिए स्टोक मैंडविले अस्पताल में ‘राष्ट्रीय स्पाइनल इंजरी सेंटर’ स्थापित किया। गुटमैन जीवन बदलने के लिए खेल की शक्ति में बहुत विश्वास करते थे और उनका मानना था कि खेल शारीरिक अक्षमता वाले लोगों के लिए चिकित्सा का एक उत्कृष्ट तरीका है, जो उन्हें शारीरिक शक्ति और आत्म-सम्मान बनाने में भी मदद करता है। अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने 29 जुलाई 1948 को रीढ़ की हड्डी की चोटों वाले द्वितीय विश्वयुद्ध के ब्रिटिश मरीजों के लिए व्हीलचेयर पर ‘स्टोक मैंडविले गेम्स’ नामक एक पहली खेल प्रतियोगिता आयोजित की, जिसका आयोजन 1948 के लंदन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन के साथ ही किया गया था। उस प्रतियोगिता में 16 घायल सैनिक और महिलाएं शामिल थी, जिन्होंने तीरंदाजी में भाग लिया था। हालांकि वह खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं थी।

1948 में पहली बार आयोजित हुए उन्हीं खेलों से पैरालंपिक आंदोलन का जन्म हुआ। 1952 में स्टोक मैंडविले गेम्स फिर से उसी स्थान पर आयोजित किए गए और तब उन खेलों में ब्रिटिश प्रतिभागियों के अलावा पूर्व डच सैनिकों ने भी भाग लिया। इस प्रकार 1952 में स्टोक मैंडविले गेम्स अपनी तरह की पहली अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल प्रतियोगिता बन गई। स्टोक मैंडविले गेम्स का आगामी कुछ वर्षों में विकास जारी रहा, जिसने ओलंपिक अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को इस कदर प्रभावित किया कि 1956 में सर गुटमैन को प्रतिष्ठित ‘फर्नले कप’ से सम्मानित किया गया, जो ओलंपिक आदर्श में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार था। इस प्रकार 1948 में घायल सैनिकों के लिए शुरू किए गए ये खेल व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो गए और 1960 में रोम में ओलंपिक खेलों के बाद ये खेल बड़े स्तर पर आयोजित किए गए। तब तक इन खेलों को स्टोक मैंडविले खेलों के रूप में ही जाना जाता था। 1960 में आयोजित हुए स्टोक मैंडविले खेलों को पहला आधिकारिक पैरालंपिक खेल आयोजन माना जाता है, हालांकि उसमें शामिल एकमात्र विकलांगता रीढ़ की हड्डी की चोट ही थी। 1960 में रोम में आयोजित किए गए इन खेलों को ही पहले पैरालंपिक के तौर पर जाना जाता है, जिसमें कुल 23 देशों के 400 व्हीलचेयर एथलीटों ने 8 खेल स्पर्धाओं में 57 पदकों के लिए मुकाबला किया था। उन खेलों को अब ‘रोम पैरालंपिक खेल’ कहा जाता है। तभी से ये खेल प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित किए जाते हैं। हालांकि उस समय इन खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के लिए सुविधाओं की भारी कमी थी, बाद के वर्षों में धीरे-धीरे उनके लिए सुविधाओं की व्यवस्था की जाती रही।

1976 के टोरंटो पैरालंपिक तक प्रतिभागियों के लिए विशेष रेसिंग व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई और विकलांगों तथा दृष्टिबाधित एथलीटों के लिए भी पहली बार खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 1980 के अर्नहेम पैरालंपिक में सेरेब्रल पॉल्सी वाले एथलीटों के लिए भी खेल प्रतियोगिताएं रखी गई। हालांकि तमाम सुधारों के बावजूद पैरालंपिक खेलों को उस समय तक भी ओलंपिक खेलों के बराबर या समानांतर नहीं माना जाता था क्योंकि वे अपने ओलंपिक समकक्ष के समान स्थल यानी उसी देश में आयोजित नहीं किए जाते थे। 1982 में पैरालंपिक आंदोलन के लिए एक मूल शासी निकाय का गठन किया गया, जिसे विकलांगों के लिए विश्व खेल संगठनों की ‘अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति’ (आईसीसी) के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा की गई थी। आईसीसी ने महसूस किया कि पैरालंपिक के लिए पैरासपोर्ट की देखभाल हेतु एक एकल शासी निकाय की आवश्यक अनिवार्यता थी, जिसके बाद आईसीसी ने पैरालंपिक खेलों को ओलंपिक खेलों के समकक्ष माने जाने के लिए कड़ी पैरवी की और आखिरकार 1988 में इसमें सफलता मिल गई।

पैरालंपिक एथलीटों को खेल उत्कृष्टता प्राप्त करने और दुनिया को प्रेरित एवं उत्साहित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 1989 में आईसीसी के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने कनाडा के रॉबर्ट डी स्टीडवर्ड। पैरालंपिक आंदोलन के वैश्विक शासी निकाय के रूप में कार्य करने के लिए 22 सितम्बर 1989 को जर्मनी के डसेलडोर्फ में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। 1999 तक आईपीसी काफी विकसित हो चुका था और यह जर्मनी के बॉन में अपने वर्तमान मुख्यालय में स्थानांतरित हो गया। अब पैरालंपिक खेल प्रतिभागियों की संख्या, टूटे हुए रिकॉर्डों की संख्या और दुनियाभर से दर्शकों की संख्या के मामले में इतिहास में बेहद सफल पैरालंपिक खेल साबित हो रहे हैं और इनमें भाग लेने वाले पैरा एथलीटों तथा देशों की संख्या हर पैरालंपिक में निरंतर बढ़ रही है। ओलंपिक खेलों के बराबर मान्यता पाने के लंबे संघर्ष के बाद पैरालंपिक खेल अब ओलंपिक के चंद दिनों बाद उसी शहर में ही आयोजित होते हैं, जहां ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है और पैरालंपिक खेलों में किसी भी खेल को दूसरे से कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। 1976 में पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित किए गए थे। ग्रीष्मकालीन खेलों की ही तरह ये शीतकालीन खेल भी हर चार साल में आयोजित किए जाते हैं और इनमें पैरालंपिक उद्घाटन समारोह तथा पैरालंपिक समापन समारोह भी शामिल होते हैं।

अपराध

डॉ. सत्यवान सौरभ

लेखक स्तंभकार हैं।

डिजिटल युग के अपराधों पर कैसे लगे लगाम?

हाल ही में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, औपनिवेशिक युग के कानूनों से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में बदलाव किया गया है। हालाँकि, नई संहिता में साइबरस्टॉकिंग और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जैसे डिजिटल युग के अपराधों से निपटने के लिए व्यापक प्रावधानों का अभाव है, जिनकी आज के तकनीकी रूप से संचालित समाज में प्रासंगिकता तीव्रता से बढ़ रही है। नई संहिता वर्तमान के डिजिटल युग बढ़ रहे साइबर अपराधों जैसे कि साइबरस्टॉकिंग, फिशिंग और डेटा उल्लंघन के दायरे को पर्याप्त रूप से परिभाषित नहीं करती हैं। भारत में फिशिंग और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के बावजूद, नए कानून ऐसे अपराधों पर मुकदमा चलाने में शामिल जटिलताओं को कवर नहीं करते हैं।

डेटा उल्लंघनों पर बढ़ती चिंता के साथ, डेटा संरक्षण और गोपनीयता उल्लंघन के लिए विशिष्ट प्रावधान प्रदान करने में नई आपराधिक संहिता विफल रही हैं। वर्तमान आपराधिक संहिताओं में डिजिटल साक्ष्यों को एकत्रित करने, उन्हें संरक्षित करने तथा न्यायलय में प्रस्तुत करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव है, जो डिजिटल अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक है। डिजिटल उत्पीड़न, विशेष रूप से महिलाओं और नाबालिगों को लक्षित करना, नए कानूनी ढाँचे में इस संदर्भ में किए गए प्रावधान अपर्याप्त है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, साइबर उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है, विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ, परंतु नई संहिता ऐसे अपराधों के लिए कड़े दंड निर्दिष्ट नहीं करती हैं। उभरती प्रौद्योगिकियों से निपटने में कमियाँ है, नए कानून उभरती हुई प्रौद्योगिकियों से संबंधित अपराधों, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी घोटाले और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग को ध्यान में नहीं रखते हैं। क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी ने डिजिटल और आभासी वातावरण में अपराधों को संबोधित करने के लिए वर्तमान में एक कानूनी ढाँचे की आवश्यकता को दर्शाया है।

हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबरस्टॉकिंग सहित साइबर अपराध के विभिन्न रूपों को लक्षित करते हुए विशिष्ट कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि पीड़ितों को प्रभावी विधिक सहायता मिल सके। सूचना और संचार नेटवर्क उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण कोरिया के अधिनियम में साइबर अपराधों के खिलाफ व्यापक प्रावधान शामिल हैं, जिसका भारत अनुकरण कर सकता है। डेटा सुरक्षा कानूनों को बेहतर बनानाः डेटा संग्रह, भंडारण और साझाकरण पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के साथ डेटा गोपनीयता विनियमों को मजबूत करना। इन कमियों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 में संशोधित किया जा सकता है और आवश्यक परिवर्तन कर लागू किया जा सकता है। न्यायालयों में डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने, प्रमाणित करने और प्रस्तुत करने के लिए मानक स्थापित करना, ताकि इसे आपराधिक कार्यवाही में यह स्वीकार्य और विश्वसनीय बनाया जा सके है।

साइबरबुलिंग और डिजिटल उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए सख्त दंड और सहायता प्रणाली प्रारंभ करना, जिसमें महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना एक अज्ञात रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से समर्थन द्वारा डिजिटल उत्पीड़न उपायों को बढ़ाती है। ऐसे कानून बनाना जो ब्लॉकचेन, उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना, ताकि तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य बनाए रखा जा सके।

यूरोपीय संघ का सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन एक लचीला ढाँचा प्रदान करता है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के विकसित परिदृश्य को संबोधित करता है। डिजिटल युग की चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत के कानूनी ढाँचे को विकसित किया जाना चाहिए। व्यापक साइबर अपराध कानूनों को शामिल करके, डेटा सुरक्षा उपायों को बढ़ाकर और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए प्रोटोकॉल को अपडेट करके, भारत एक मजबूत और उत्तरदायी कानूनी प्रणाली सुनिश्चित कर सकता है। यह विकास तेजी से डिजिटल हो रहे विश्व में नागरिकों की सुरक्षा और समाज में विश्वास, सुरक्षा और न्याय को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

वक्रोक्ति

मनमोहन हर्ष

लेखक व्यंग्यकार हैं।

डाटाखोरी में लिप्त मिसकॉलचियों की जमात

‘लेने के देने’ भी पड़ सकते हैं। हमें तो जब से इस ‘हटकर-बयानी’ का रोग लगा है तब से ही ‘हटकरजी’ की ओर से उनकी बातों को बतंगड़ में तब्दील करने के लिए कुछ अपनी ‘नमक-मिर्ची बुरकाने का लाइसेंस’ उन्होंने ही राजी-राजी दे रखा है। वैसे हमें तो अब इस बात का ‘छोटा-मोटा मुगालता’ हो चला है कि गोया हम उनकी ‘बतकहियो की बही’ आपके समक्ष बार-बार खोलकर नहीं बांचते तो उनकी ‘सूरत और सीरत’ को नित नए तरीके से संवारने और ‘भेजाफ्राई’ करने वाली उनकी स्टाइल को झेलने वाला कोई दूसरा ‘माई का लाल’ उनको नहीं। जबसे आप सुधी पाठकों की दृष्टि ‘हटकरजी’ के पुराण के इस एडिशन में ‘डाटाखोर-डाटाटोर’ के अजीबोगरीब शीर्षक पर पड़ी होगी, आप सोच रहे कि अब तक इस नए तिलिस्म का खुलासा करने की बजाय हम भी ‘कंटीनुअसली’ बेसिर पैर की हांके ही जा रहे है।

हमारे ‘हटकरजी’ की शोहरत शनैः शनैः ‘ग्लोबल वार्मिंग’ की मानिंद ब्रह्मांड में पंख पसार रही है। आपसे सचीमुची में कह रहे है कभी-कभी तो हमें यह डर सताने लगता है कि ‘हटकरजी’ हमारी पकड़ और जकड़ से निकलकर अपना दीगर ‘ठीया’ (ठिकाना) न बना लें। अब आपको का बताए ‘हटकरजी’ षिखा धारण तो नहीं करते, पर किस्सागोई के किले के षिखर पर वे अक्सर सिक्का जमाते है। फिर करीने से बाकायदा किस्सों को बारी-बारी से चोटी पकड़-पकड़कर ‘बातपोषी’ के बाजार में उतारते हैं। ऐसे में इनसे दिल लगा बैठने, उनसे नुक्ताचीनी करने या दो-दो हाथ करने की मजबूरी अपनी तो नियति बन चुकी है। यह एहसास ‘हटरकजी’ के हमसे छिटकने का डर पल में काफूर कर देता है। और हम ‘संतोष के समंदर’ में डुबकी लगाते हुए निश्चिंत हो जाते है कि न तो ‘हटकरजी’ को अपनी ‘उलटबांसियों को उगलने’ के लिए हमारे जैसी ‘कम्फर्टजोन’ वाली कोई ठौर मिल सकती है और ना ही हमारे पास अपने कीमती समय के इत्तर उनकी शरण में समय गुजारने से बड़ा ‘एंटरटेनमेंट का जोन’ हो सकता है। हम आपको फिर से ‘सोलह बिसवा सावधान’ किए देते है कि हमारी बातों से आप ‘हटकरजी’ जैसी महान शख्सियत को कोई ‘टाइमपास मूंगफली’ समझने की भूल गलती से भी मत कर बैठना। ये आपका हाजमा बिगाड़ने और बैठे ठाले ‘आ बैल मुझे मार’ जैसी बिना बुलावे की ‘मुसीबत को दावत’ देने वाली ‘भारी और भयंकर भूल’ साबित हो सकती है। ‘लेने के देने’ भी पड़ सकते है। हमें तो जब से इस ‘हटकर-बयानी’ का रोग लगा है तब से ही ‘हटकरजी’ की ओर से उनकी बातों को बतंगड़ में तब्दील करने के लिए कुछ अपनी ‘नमक-मिर्ची बुरकाने का लाइसेंस’ उन्होंने ही राजी-राजी दे रखा है। वैसे हमें तो अब इस बात का ‘छोटा-मोटा मुगालता’ हो चला है कि गोया हम उनकी ‘बतकहियो की बही’ आपके समक्ष बार-बार खोलकर नहीं बांचते तो उनकी ‘सूरत और सीरत’ को नित नए तरीके से संवारने और ‘भेजाफ्राई’ करने वाली उनकी स्टाइल को झेलने वाला कोई दूसरा ‘माई का लाल’ उनको नहीं। जबसे आप सुधी पाठकों की दृष्टि ‘हटकरजी’ के पुराण के इस एडिषन में ‘डाटाखोर-डाटाटोर’ के अजीबोगरीब शीर्षक पर पड़ी होगी, आप सोच रहे कि अब तक इस नए तिलिस्म का खुलासा करने की बजाय हम भी ‘कंटीनुअसली’ बेसिर पैर की हांके ही जा रहे है। पर इसमें अपुन का ‘तिल भर का भी दोष’ नहीं है। ‘हटकरजी’ के हर एपिसोड में ये सब ‘नैचुरली’ घटित हो जाता है। ये हमारे ऊपर ‘हटकरजी’ के प्रकांड प्रकोप के ‘पुछल्ले’ का ‘क्षणिक प्रभाव’ मात्र ही है।

आओ अब लौट चले ‘मौका-ए-वारदात’ की ओर...। अपुन का मतलब ‘हटकरजी’ की ‘डाटाखोरी और डाटाटोरी’ की नई थ्योरी से माथाफोड़ी के लिए तैयार रहे। वैसे डाटाखोर का मतबल तो आप कुछ-कुछ समझ गए होंगे। ये ‘डाटाटोर’ फिर कौनसी बला है? का कीड़ा अगर आपके दिमाग में ‘किलोल’ कर रहा हो तो हम इतना ईशारा कर देते है कि हमारे उधर पशुओं को ‘हांकना’, ‘टोरना’ कहलाता है। हो सकता है कि ‘डाटाटोर’ का शब्द ‘हटकरजी’ ने इसी से ईजाद किया हो। हटकरजी’ फरमाते है कि ‘‘एक दौर था जब ‘मिसकॉलचियों (दूसरो के मोबाईल पर मिस कॉल करने वाली जमात) ने उनको जमकर छकाया-सताया। कॉल करने की अच्छी-खासी कीमत वाले उस कालखंड में ये ‘मिसकॉलची’ गाहे-बगाहे अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए ‘मिस्ड कॉल’ के अस्त्र का कुषलता पूर्वक इस्तेमाल किया करते थे। आप भी सोच रहे होंगे कि ‘मिस्ड कॉल’ के करतबों के दौर को बीते जब अरसा हो गया तो बेवजह ये ‘पोथी-पानड़ा’ फिर से क्यों खोला जा रहा है? ठीक ऐसी ही सोच के साथ हमने ‘हटकरजी’ को टोकते हुए पूछ लिया कि अफीम का सेवन करने वालो के लिए ‘अफीमची’ जैसा शब्द तो हमने सुन रखा है, हो सकता है कि आपने इसी तर्ज पर ‘मिसकॉलची’ की उपमा घड़ी हो, पर अब जब सभी ‘कॉल्स’ फ्री है तो गड़े ‘मुद्दों को उखाड़कर’ काहे खामोख्याह सबकी ‘मगजमारी’ कर रहे हो? ‘बतकही की बांसुरी’ बजाते ‘हटरकजी’ के बढ़ते कदमों पर ब्रेक लगाने वाली हमारी इस ‘मासूम गुस्ताखी’ के बाद हमें लगा कि आज तो अपुन की खैर नहीं, भरी महफिल में हमारी शामत आने वाली है। मगर ‘सरप्राईजिंगली’ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट ‘हटकरजी’ का रोम-रोम पुलकित होने लगा। कातिल मगर मीठी और करूणा से भरी मुस्कान के साथ उन्होंने सफाचट सिर के नीचे दमकती भौंहों से नजरे हमारी ओर तरेरी। मगर हमेशा की तरह भयाक्रांत होने के बजाए हमें लगा जैसे हमारे ऊपर उनकी ‘कृपादृष्टि’ की कोई लॉटरी खुल गई है। बीच महफिल ‘हटकरजी’ अपनी गद्दी छोड़कर सहसा उठे, फिर अनायास ही हमारी बाजू में आ टिके। अपुन के सिर पर ऐसे हाथ फिरा रहे थे, गोया अपना टनों आशीर्वाद उंडेल रहे हो। ‘हटकरजी’ ने उनकी वेवलेंथ को कुछ-कुछ पकड़ते हुए ‘अफीमची’ और ‘मिसकॉलची’ के बीच तारतम्य जोड़ने का करिश्मा कर गुजरने के लिए हमारी पीठ थपथपाई। ‘हटकरजी’ ने अपनी नई रिसर्च स्टोरी ‘डाटाखोरी-डाटाटोरी’ से पर्दा उठाते हुए सवाल दागा कि ‘‘क्या आप लोगों को नहीं लगता टेलीकॉम इंडस्ट्री में आए क्रांतिकारी बदलावों के बीच ‘मिस्ड कॉल कल्चर’ और ‘मिसकॉलचियों’ की जमात आज भी मजे से ‘इमली के पत्ते पर डंड पेलने’ में मशगूल है?’’ भला अब भी कोई क्यों और क्योंकर ‘मिस्ड कॉल’ से दिल लगाए बैठा हो सकता है, यह सोचकर हमारे मन में ‘हटकरजी’ के सठियाने की हद पार करने का शक घर करने लगा। मगर ‘हटकरजी’ ने कथानक के अगले ‘प्लॉट’ में फरमाया कि ‘मिसकॉलचियों’ की जमात आजकल इंटरनेट के डाटा की ‘डाटाखोरी-डाटाटोरी’ के धंधे में लिप्त है। ‘‘कोई गुजरे जमाने के इन ‘मिसकॉलचियों’ के मोबाईल की तलाशी ले तो इंटरनेट डाटा की मुफ्तखोरी के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों से लेकर पड़ौसियों और ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, बैंक तथा रेलवे स्टेशन जैसे न जाने कहां-कहां के वाई-फाई नेटवर्क के पासवर्ड उन्होंने ‘सइजम’ (सेव) कर रखे है। एक ओर जमाना इंटरनेट डाटा के लिए भारी-भरकम कीमत चुकाते हुए अपनी जेब खुशी-खुशी ढीली करता है। वहीं ये ‘डाटाखोर-डाटाटोर’ टेलीकॉम कम्पनियों की ‘जेबतराशी कला’ को ‘ठेंगा दिखाकर’ खुले आम अपना ‘उल्लू सीधा’ रहे हैं।’’ वाकई में ‘हटकरजी’ ने हमेशा की तरह अपने ‘तर्कों के तरन्नुम’ से सबको ‘चारों खाने चित्त’ कर दिया।

शिक्षकों के सम्मान में डागा फाउंडेशन ने फिर दिखाई कृतज्ञता

5 सितंबर को 5100 शिक्षक होंगे सम्मानित

बैतूल। जिले में डागा फाउंडेशन द्वारा हर साल की तरह इस वर्ष भी शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 5100 शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। डागा फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा यह सम्मान शिक्षकों के निवास और कार्य स्थलों पर जाकर किया जाएगा, जिसमें वे शिक्षकों को सम्मानित कर उनकी मेहनत और कर्तव्यनिष्ठा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।

उल्लेखनीय है कि डागा फाउंडेशन हर वर्ष शिक्षक दिवस पर यह सम्मान कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे शिक्षकों के प्रति आदर और सम्मान की भावना प्रकट होती है। फाउंडेशन के सदस्य मानते हैं कि शिक्षक समाज के मार्गदर्शक होते हैं, और उनकी सेवाओं का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करना समाज का कर्तव्य है। फाउंडेशन की इस पहल से ना केवल शिक्षकों को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि समाज में उनके योगदान को भी पहचान मिलती है। इस सम्मान कार्यक्रम में डागा फाउंडेशन के सैकड़ों सदस्य शामिल होते हैं, जो विभिन्न स्कूलों और शिक्षकों के घर जाकर उन्हें सम्मानित करते हैं। इस पहल के पीछे फाउंडेशन की यह सोच है कि शिक्षकों की मेहनत को सही सम्मान मिले और उन्हें यह महसूस हो कि उनके योगदान को समाज ने सराहा है। डागा फाउंडेशन की यह परंपरा सालों से चली आ रही है, और हर साल शिक्षक दिवस पर इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी 5 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में फाउंडेशन के सदस्यों ने पूरी तैयारी कर ली है और शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए उत्सुक हैं। फाउंडेशन के इस प्रयास ने बैतूल के शिक्षा जगत में एक अनूठी पहचान बनाई है और इसे समाज के सभी वर्गों से सराहना मिली है।

नवरास गरबा महोत्सव का भव्य शुभारंभ

बैतूल। रविवार शिवचतुर्दशी को नटराज डांस सेंटर बैतूल द्वारा नचरास गरबा महोत्सव का भव्य शुभारंभ नगर पालिका बैतूल के सेवानिवृत्त ऑडिटर बंटी वासनिक के आतिथ्य में किया गया । जिसमें नटराज डांस सेंटर के कलाकार एवं उनके अभिभावकों सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बंटी वासनिक? ने बताया कि नटराज डांस सेंटर के द्वारा नवरात्रि के अवसर पर नवराज गरबा महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है जो कि निश्चित ही गरबा प्रेमियों को एक अच्छा मंच मिलेगा वहीं नगरवासियों को नवरास गरबा महोत्सव का आनंद लेने का मौका मिलेगा । उन्होंने बताया कि नटराज डांस केंद्र द्वारा समय-समय पर इस तरह के आयोजन करते रहते हैं जिससे यहां के कलाकारों को मंच मिलता है और उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर भी मिलता है। श्री वासनिक ने बताया कि 1 सितंबर से नवराज गरबा महोत्सव का शुभारंभ किया गया है जो की समाचार से रात्रि 9ः00 बजे तक प्रतिदिन चलेगा और पूरे एक महीने के लिए आयोजन किया गया है।

नवराज गरबा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर डा. उदय चकोटिया, अर्चना वर्मा, (हिन्दू वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष), कृष्णा पान्से सर, श्याम खातरकर सर ने अपनी सहभागिता दी । शुभारंभ में रत्नमाला मेम, सरिता मेम, मोंटी सर, सन्जु सर ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों एवं सभी कलाकारों का नटराज डांस सेन्टर की डायरेक्टर शीतल मेम दुर्गेश सर के द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

चक्रवाती तूफान ने तबाह की पांच गांवों में मक्के की फसल

बैतूल। जिले के प्रभात पट्टन विकासखंड में स्थित बोरपेंड और चारसी ग्राम पंचायत के किसानों की मक्के की फसल चक्रवाती तूफान के कहर से बुरी तरह तबाह हो गई है। खेतों में मक्के की लहलहाती फसलें अब बिछी नजर आ रही हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाड़े ने मौके पर पहुंचकर बर्बाद फसल का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही एसडीएम से तुरंत सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की।

नायब तहसीलदार को सर्वे के निर्देश मुलताई एसडीएम अनीता पटेल ने जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाड़े की बातों को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार प्रभात पट्टन को जल्द से जल्द सर्वे करवाने के निर्देश देने का आश्वासन दिया। मिली जानकारी के अनुसार गोंडी, धनोरी, टोपीढाना, बोरपेंड, और चारसी गांवों के किसानों की मक्के की फसल बर्बाद हो गई। किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। बोरपेंड के किसान लीलाधर ठाकरे ने अपनी पांच एकड़ की मक्के की फसल गंवाई है, उन्होंने बताया कि उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसी प्रकार, अजाबराव कनाठे की भी पांच एकड़ की फसल चक्रवात की भेंट चढ़ गई। हरि कोलनकर, शंकर ठाकरे, भदूजी ठाकरे, और रमेश बोफते सहित कई किसानों ने बताया कि लगभग 50 एकड़ की मक्के की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि अगर तुरंत सर्वे नहीं किया गया, तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस संकट की घड़ी में जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाड़े ने किसानों के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने बोरपेंड और चारसी गांव के किसानों से बातचीत के दौरान फसल के नुकसान की स्थिति को समझा और तत्कालीन समाधान के लिए एसडीएम से चर्चा की। इस दौरान मौके पर रमेश गव्हाड़े, उत्तम गव्हाड़े, अभिषेक राउत, सीताराम सोलंकी सहित अन्य किसान उपस्थित थे। किसानों का कहना है कि वे इस नुकसान से अकेले उबरने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में उन्हें सरकार की मदद की जरूरत है।

नपा को दिखता है सिर्फ हास्पिटल और कॉलेज के सामने का अतिक्रमण

पूरे शहर में फैला हुआ है अवैध अतिक्रमण का जाल, नागरिकों ने की कार्यवाही की मांग

बैतूल। अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका बैतूल को सिर्फ जिला अस्पताल और कॉलेज चौक ही दिखता है। आए दिन नगर पालिका की टीम इन स्थानों पर जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करती है। नगर पालिका की इस कार्यवाही से नागरिकों को लगने लगा है कि इन्हें शहर के दूसरे बड़े अतिक्रमण नहीं दिखते, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। आज नगर पालिका की टीम ने जिला अस्पताल के सामने लगी गुमटियों को हटाया। कुछ गुमटियों को स्वेच्छा से हटाने का समय भी दे दिया। इसके बाद टीम परशुराम चौक (कॉलेज चौक) पहुंची और यहां लगी फलों की दुकानों को हटाया गया। दुकानदारों का कहना है कि नगरपालिका को कोठीबाजार में जाल की तरह फैला अतिक्रमण नहीं दिखता है, न ही उन पर इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है। नगरपालिका सिर्फ छोटे दुकानदारों को अपना पावर दिखाकर कार्रवाई करते है और बडो पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है।

आखिर क्यों करती है नपा दुकानदारों से भेदभाव- नगर पालिका की कार्रवाई वाई साफ दिखती है कि वे अतिक्रमण हटाने में भेदभाव करती है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि वे किसी तरह से अपना परिवार पालते है उसके बाद भी नगरपालिका उनकी दुकान को हटाना तो छोड, दुकान तक ही तोड देते है। दुकानदारों का कहना है कि अगर नपा को अतिक्रमण हटाना है तो कोठी बाजार, सदर, गंज जहां बड़े लोग बैठे है उनका भी अतिक्रमण हटाया जाए, परन्तु नपा उनके डर से उनका अतिक्रमण नहीं हटाती है।

पांचवीं बार हटाए गए अतिक्रमण- नगर पालिका की टीम में शामिल अधिकारी का कहना है कि परशुराम चौक पर अतिक्रमण हटाने की यह पांचवीं बार कार्यवाही हुई है। जहां पर मूर्ति लग रही है वहां पर फलों की दुकान लग गई थी। जिसे आज हटाया गया है। इसके बाद जेएच कॉलेज के सामने भी दुकानें लगी थी उन्हें हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा परशुराम चौक से बाबू चौक तक सड़क किनारे लगने वाली सब्जी की दुकानें हटाने के लिए समझाइश दी गई है कि वे सड़क के किनारे दुकानें ना लगाए। अगली बार उनकी दुकानें हटाने के लिए सख्त कार्यवाही की जाएगी।

तीसरी बार हुई कार्यवाही- जिला अस्पताल की बाउंड्रीवाल के किनारे लगी गुमटियों को सोमवार नगर पालिका की टीम ने सख्ती से हटाने की कार्यवाही की। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल के सामने होने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए तीसरी बार कार्यवाही की गई। कुछ गुमटियों को जेसीबी मशीन से हटाया गया। इसके बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत वागद्रे मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्वेच्छा से दुकानें हटाने के लिए नगर पालिका के अधिकारियों से बात की और इन दुकानदारों को स्वेच्छा से दुकानें हटाने का समय दिया गया।

दोनों जगह ही क्यों होती है कार्यवाही ?- नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर शहर के जागरूक नागरिकों का कहना है कि पूरा शहर अतिक्रमण के जाल में फंसा हुआ है जिससे नागरिकों को आए दिन परेशानी होती है बावजूद इसके नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से परहेज किया जाता है। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की टीम को सिर्फ कालेज चौक और हास्पिटल के पास का ही अतिक्रमण दिखाई देता है जबकि शहर के अन्य हिस्सों में फैला अतिक्रमण हटाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है इससे लोगों में नाराजगी व्याप्त हो रही है।

तीन साल से सूख रही फसलें, किसानों ने जनसुनवाई में दी आंदोलन की चेतावनी

पाइपलाइन की गहराई से लेकर ओएमएस की सुरक्षा तक अनदेखी, किसानों ने मांगा न्याय

बैतूल। जिले के पारसडोह जलाशय की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना में हो रही अनियमितताओं से त्रस्त होकर 42 गांवों के किसानों ने मंगलवार को जिला जनसुनवाई में कलेक्टर से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाया और ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनके खेतों में तीन साल से पानी नहीं पहुंच पाया है, जिससे उनकी फसलें सूख गईं। इस हालात में अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं और भविष्य में परियोजना के सही ढंग से संचालित होने की गारंटी चाहते हैं।

ज्ञापन में किसानों ने स्पष्ट किया कि पारसडोह सिंचाई परियोजना का काम अभी अधूरा है और ठेकेदार द्वारा निर्धारित गहराई पर पाइपलाइनें नहीं गाड़ी गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने ठेकेदार को बिना काम पूरा हुए कंपलीशन सर्टिफिकेट (सीसी) जारी किया या परियोजना को हैंडओवर किया, तो वे इसे प्रशासन की साजिश मानते हुए विरोध करेंगे। किसानों का कहना है कि इस मामले में ठेकेदार के साथ ही विभाग के अधिकारी भी दोषी होंगे।

प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग- पूर्व भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भवानी गावंडे, किसान नेता मकरध्वज सूर्यवंशी, गुलाब देशमुख (आस्टा), चिंताराम हारोडे (काजली), अलख निरंजन बरोदे (मासोद), और जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाडे सहित अन्य किसानों ने मंगलवार को बैतूल कलेक्टर जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपा। किसानों ने पारसडोह जलाशय की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में हो रही अनियमितताओं पर कड़ा विरोध जताते हुए विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की।

किसानों ने बताया कि वे लगातार तीन वर्षों से रबी की फसलें लगा रहे हैं, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2021-22, 2022-23 और अब 2023-24 में भी गेहूं की फसल सिंचाई के अभाव में सूख गई। इसके लिए उन्होंने कई बार विभागीय अधिकारी शिवकुमार नागले (उपयंत्री), मनोज चौहान (अनुविभागीय अधिकारी) और विपिन वामनकर (कार्यपालन यंत्री) से संपर्क किया, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिला। ठेकेदार के अधिकृत अधिकारी देवेश नागले ने भी किसानों को बार-बार आश्वासन दिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।

किसानों ने जनसुनवाई में कहा कि उन्हें सीएम हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से भी कोई राहत नहीं मिली। अधिकारियों ने केवल आश्वासन देकर मामला बंद करवा दिया, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। किसानों का कहना है कि प्रति हेक्टेयर लगभग 95 हजार रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें जुताई, बीज और खाद का खर्च भी शामिल है।

विभाग और ठेकेदार पर गंभीर आरोप

किसानों ने विभाग और ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों को तय गहराई में नहीं रखा गया, जिससे खेतों की जुताई के दौरान पाइपलाइनें टूट जाती हैं। ओएमएस चक पेटी का बेस कंक्रीट नहीं किया गया, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में है। इसके अलावा, ओएमएस की सुरक्षा के लिए किसी भी जल मित्र या एफआरओ की नियुक्ति नहीं की गई है।

किसानों ने कहा कि ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से योजना के तहत 42 गांवों के एक भी किसान को समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिल पाया। उन्होंने मांग की कि योजना का सही ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का निरीक्षण और तकनीकी परीक्षण किया जाए।

मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो करेंगे उग्र आंदोलन

किसानों ने कलेक्टर से यह भी कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना, जो एक समय में किसानों के लिए वरदान मानी जा रही थी, अब उनकी पीड़ा का कारण बन गई है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ सिंचाई प्रणाली कही जाने वाली पारसडोह परियोजना, अगर ऐसे ही चली, तो बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी और इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेदार होगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के खिलाफ बैतूल में विरोध की लहर, सभी विभागों के कर्मचारी शामिल

जिलाध्यक्ष रवि सरनेकर के नेतृत्व में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, एनपीएस से भी खराब है यूनिफाइड पेंशन स्कीम

बैतूल। जिले में आज 3 सितंबर को शिक्षकों ने एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) और यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि एनपीएस से भी खराब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लागू करना उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करे, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय स्थिति सुरक्षित हो सके।

जिलाध्यक्ष रवि सरनेकर ने बताया कि एनपीएस में पहले से ही कई खामियां थीं, जिसके चलते उनका भविष्य सुरक्षित नहीं था। अब, जब सरकार ने एनपीएस के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है, तो स्थिति और भी गंभीर हो गई है। उनके अनुसार, यह नई योजना न केवल उनकी पेंशन को और अनिश्चित बनाती है, बल्कि उनकी वित्तीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।

रवि सरनेकर ने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों का गुस्सा इस बात से है कि सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि 2 से 6 सितंबर तक, मध्यप्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर एनपीएस और यूपीएस का विरोध कर रहे हैं। काली पट्टी पहनने का यह कदम इस बात का प्रतीक है कि कर्मचारी सरकार की नई पेंशन योजना से बेहद असंतुष्ट हैं। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार नई पेंशन योजनाओं को लागू कर केवल अपने बजट को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है, जबकि कर्मचारियों के भविष्य के प्रति उदासीनता दिखा रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं करती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे और भी उग्र कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। इस आंदोलन में सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं।

कलेक्टर ने भीमपुर में 101 प्रकरणों पर की जनसुनवाई

ग्राम डोरी, खामापुर, आदर्श धनोरा में नल जल योजनाओं का किया निरीक्षण

बैतूल। जनसुनवाई मात्र औपचारिकता नहीं गंभीरता पूर्वक शिकायतों का निराकरण करें। यह बात कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को भीमपुर के मंगल भवन में आयोजित जनसुनवाई के संदर्भ में अधिकारियों से कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मंशा के अनुरूप राज्य शासन द्वारा जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन की छोटी बड़ी समस्याओं का निराकरण करना है। जनसुनवाई के तहत 101 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को 7 दिनों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भैंसदेही श्री शैलेन्द्र हनोतिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भीमपुर श्री अभिषेक वर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने ग्रामीणों से कहा कि प्रत्येक मंगलवार को विकासखंड स्तर पर जनसुनवाई की जा रही है, जिससे बैतूल जिला स्तर पर जनसुनवाई में आकर ग्रामीणों को अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़ेगा। ग्रामीण विकासखंड स्तर पर ही अपनी समस्याओं का निदान करा सकेंगे। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने विकासखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम स्तरीय कार्यालय का सतत दौरा करते रहे। कार्यालय में सभी की उपस्थिति प्रातः 10 बजे सुनिश्चित कराए। भ्रमण के दौरान निरीक्षण टीप अंकित करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दिए गए।

खामापुर एवं आदर्श धनोरा में नल जल योजना का किया निरीक्षण- जनसुनवाई में पीएचई विभाग के अधिक आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी एकाएक सीधे मौका स्थल पर योजना का क्रियान्वयन देखने ग्राम डोरी, ग्राम खामापुर, आदर्श धनोरा पहुंचे। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजनाओं का निरीक्षण कर नल जल से पानी प्राप्त होने की स्थिति की ग्रामीणों से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान नल जल से ग्रामीणों को पानी प्राप्त नहीं होने तथा कार्य समय सीमा में पूर्ण नहीं किए जाने पर पीएचई विभाग व ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाई तथा 3 दिवस में तत्काल कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करने के निर्देश पीएचई विभाग के अधिकारियों को दिए।

विभाग से संबंधित शिकायत एजेंसी मेसर्स कोठारी इन्फ्रास्ट्रक्चर, खंडवा के द्वारा 12 ग्रामों में कार्य किया जा रहा है। जिसमें पलासपानी, डोरी, खामापुर, बेला, बक्का, टिटवी, बाटलाकला, देसली इन ग्रामों मे पेयजल चालू न करने पर शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत को कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया।

संयुक्त कलेक्टर ने 72 आवेदनों पर की जनसुनवाई

बैतूल। संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में 72 प्रकरणों पर जनसुनवाई की। इस दौरान श्री अहमद ने संबंधित अधिकारियों प्राप्त आवेदनों का गंभीरतापूर्वक निराकरण किए जाने के निर्देश प्रदान किए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्रीमती तृप्ती पटेरिया, एसडीएम श्री राजीव कहार सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

ग्रामीणों ने की सड़क निर्माण की मांग- ग्राम पंचायत बांसपानी के ग्राम ठानी के ग्रामीणों ने जनसुनवाई में आवेदन के माध्यम से सडक़ निर्माण कराए जाने की मांग की। आवेदन में ग्रामीणों ने उल्लेख किया है कि उनके ग्राम को तीन सडक़ नेशनल हाइर्दवे को जोड़ती है। ग्राम ठानी से पंचायत भवन तक 1 किलोमीटर, ग्राम ठानी से उड़दन आरटीओ कार्यालय 2 किलोमीटर तथा ग्राम ठानी से साकादेही तक 2 किलोमीटर की सडक़ों की स्थिति बेहद दयनीय है। बारिश के दौरान सडक़ों पर बड़े-बड़े गड्ढों में जलभराव हो जाता है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते है। स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच, सचिव से लेकर जनप्रतिनिधियों को भी समस्या से अवगत कराया लेकिन अब तक निराकरण नहीं हुआ है।

संक्षिप्त समाचार

बहनों के लिए मददगार साबित हो रही लाड़ली बहना योजना

सीहोर (निप्र)। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं की सहायता के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार दो सौ पचास रूपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। जिसे महिलाएं अपनी आवश्यकतानुसार खर्च कर रही है।सीहोर निवासी श्रीमती रचना ठाकुर भी लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित महिलाओं में से एक है। श्रीमती रचना बतातीं हैं कि लाड़ली बहना योजना से मुझे जो राशि मिली है, उसे मैं अपने बच्चों एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग कर रही हूं। श्रीमती रचना कहतीं हैं कि अब मुझे अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए किसी से पैसे नही मांगने पड़ते। उन्होंनें बताया कि लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित हो रही है। लाड़ली बहना योजना के लिए श्रीमती रचना ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है।

उन्नत खेती और अधिक उत्पादन के लिये तकनीकी ज्ञान जरूरी

सीहोर (निप्र)। किसान भाई उन्नत खेती और अधिक उत्पादन के लिये तकनीकी ज्ञान से स्वयं को समृद्ध करें। जिले के किसान को उन्नत खेती करने के तरीके एवं खेती को लाभ को लाभारी बनाने कृषि अधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिक अपने-अपने ग्रमीण क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान किसानों को आधुनिक खेती कैसे करें, गुणवत्तायुक्त उत्पादन कैसे हो, किसानों को अपनी उपज का अधिक से अधिक मूल्य कैसे प्राप्त हो, इन सभी के बारे में समय-समय पर बताये जा रहे है। किसान भाई उन्नत खेती करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताये गये नये-नये तरीके अपनाए जिससे अधिक से अधिक खेती में लाभ लें, जिससे उत्पादन वृद्धि में मदद मिल सके। किसान परिवार के बच्चे अब उच्च शिक्षित हो रहे हैं। हम सभी उन्हें खेती के साथ कृषिगत व्यापार और उद्योग के लिये भी प्रोत्साहित करें। सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये सतत प्रयासरत है। किसानों के अच्छे दिन आये हैं। इसीलिये बेहतर योजनाएँ बना कर लाभान्वित किया जा रहा है। अब सरकार और किसानों के मध्य कोई बिचौलिया नहीं है। गाँव को विकास के लिये समुचित राशि उपलब्ध कराना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गाँव के विकास के लिये क्रांतिकारी साबित हुई है।

विहिप ने स्थापना दिवस मनाया

पिपरिया(निप्र)। पिपरिया विश्व हिंदू परिषद पिपरिया जिला का षष्ठीपूर्ति समापन कार्यक्रम माँ कर्मा मंगल भवन में हुआ। विहिप स्थापना दिवस एवं विहिप षष्ठीपूर्ति वर्ष समापन कार्यक्रम पर प्रांत के प्रखंड केन्द्रों पर व्यापक जनजागरण कार्यक्रम के अंतर्गत विहिप की 60 वर्ष की उपलब्धियां वर्तमान में राष्ट्रधर्म एवं हिंदू समाज के समक्ष चुनौतियों तथा उनके निराकरण के संबंध में गोष्ठी की। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में जुगराजधर द्विवेदी विशेष संपर्क क्षेत्र प्रमुख थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शक्तिधाम पीठाधीश्वर दिवाकर महाराज राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक मनोहरलाल पटेल, संत गोपालदास त्यागी उमरधा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान विहिप के विभाग संगठन मंत्री योगी वीरसिंह, विभाग मंत्री चैन सिंह पटेल, विभाग संयोजक श्रीकांत पटेल, जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र गुप्ता, जिला मंत्री महेन्द्र साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेन्द्र भार्गव, पूर्व मंत्री शेरसिंह रघुवंशी, कोषाध्यक्ष धनराज तिवारी सहित विहिप के बनखेड़ी, सोहागपुर, पिपरिया, पचमढ़ी के कार्यकर्ता शामिल हुए। संचालन जिला सहमंत्री धुव्रकुमार उरहा, जिलामंत्री महेन्द्र साहू ने किया। आभार सत्येन्द्र गुप्ता ने व्यक्त किया।

हिंदी दिवस पर पचमढ़ी में हिंदी काव्य महोत्सव मनेगा

नर्मदापुरम (निप्र)। समाजसेवा, कला, साहित्य, संस्कृति को समर्पित संस्था नर्मदा आव्हान सेवा समिति हिन्दी दिवस पर पचमढ़ी में 14 व 15 सितंबर को दो दिवसीय हिन्दी काव्य महोत्सव मनाया जाएगा।

आरजीपीवी भोपाल घोटाले के तार सोहागपुर में, दो आरोपियों के घरों में ईडी का छापा,बाहर रहे बंदूकधारी

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। आरजीपीवी भोपाल घोटाले के तार सोहागपुर में।कल इसी संबंध में ईडी का छापा दलित संघ के सचिव रत्न उमरे के सरदार वार्ड स्थित में छापा मारा गया। उनके निवास के बाहर केन्द्रीय बल तैनात रहा। इसी संदर्भ को लेकर नगर से करीबन चार किलोमीटर दूर ग्राम गुंदराई में सुनील रघुवंशी के घर भी ईडी ने छापा मारा। बताया जाता है कि ईडी की टीम अलसुबह सोहागपुर आ चुकी थी। लेकिन घर में ताला बंद रहने के कारण ईडी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने जानकारी एकत्रित की । जैसे ही शाम को आरोपी रतन उमरे के परिजन भोपाल से आए। वैसे ही घर में दबिश दे दी गई। आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या क्या दस्तावेज छापे में मिले हैं।

दलित संघ - दलित संघ संस्था की स्थापना स्वगीर्य गोपाल नारायण आवटे ने की थी। उक्त संस्था ने एनजीओ के माध्यम से जिले में अपनी उत्कृष्टता के साथ दलितों,बैलपारदियो, विकलांग, दृष्टिहीनो एवं वंचित समाज के लिए कई उल्लेखनीय कार्य करके प्रशंसा प्राप्त की थी। इसी तारतम्य में डा- जीएन आवटे को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में राष्टपति अब्दुल कलाम ने दलित संघ के सानिध्य में विकलांग बच्चों ने भेंट की थी। लेकिन हाल में आरजीपीवी में करोड़ों रुपए की आर्थिक अनियमितताओं के कारण दलित संघ की साख लगभग समाप्त हो गई है।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय - आरजीपीवी घोटाले के मामले में नया खुलासा में वहां के अकाउंट से दलित संघ सोहागपुर के खाते में 9.50 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। चर्चित है कि करोड़ों रुपए व्यापारियों को बांटने के अलावा काफी रकम उसने अपने खाते में ट्रांसफर कर दी थी।यह खुलासा आरजीपीवी के अकाउंट से दलित संघ के खाते में ट्रांसफर हुए 9.50 करोड़ रुपए मामले की जांच कर भोपाल की गांधीनगर पुलिस ने किया था। जिसमें पुलिस ने दलित संघ के सचिव रतन उमरे एवं कोषाध्यक्ष अशोक चौरसिया को आरोपी बनाया था।

अभी तक गिरफ्तार - आरजीपीवी घोटाले में सोहागपुर से दलित संघ के सुनील रघुवंशी , दलित संघ सचिव रतन उमरे सोहागपुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्ञातव्य है कि अभी दलित संघ सोहागपुर का कोषाध्यक्ष अशोक रघुवंशी अभी पुलिस के हाथ नहीं आया है ।इधर पता चला है कि राजधानी भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए करीब 19.48 करोड़ रुपये के घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तत्कालीन रजिस्ट्रार आरएस राजपूत के निवास पर छापा मारा है ।मामले में ईडी टीम ने दस्तावेज एकत्रित किए हैं।

पोला अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा में लगाई डुबकी किया दानधर्म, घाट पर तैनात होमगार्ड के जवान

हरदा(निप्र)। पोला व सोमवती अमावस्या पर सोमवार को जिले के हंडिया, छीपानेर, गोयत, लछौरा सहित अन्य नर्मदा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद गरीबों को दानपुण्य कर भगवान रिद्धनाथ व सिद्धनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। तवा डैम से पानी छोड़ने से हंडिया में भी नर्मदा में काफी पानी बढ़ गया है। इससे हादसे की आशंका के चलते पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए है। नर्मदा के जल में बैरिकेड्स लगाकर श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोका जा रहा है। होमगार्ड एवं पुलिस के जवान नावों के माध्यम से स्थिति पर नजर बनाए है। वहीं पटवारी एवं पुलिस के जवान भी घाटों पर मौजूद है। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हुआ स्नान पूजा का क्रम दोपहर बाद तक जारी रहेगा। ।श्रद्धालुओं ने मंदिर, आश्रम, धर्मशाला सहित अन्य स्थानों पर रात गुजरने के बाद अलसुबह ब्रह्म मुहूर्त से स्नान पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया था। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी घाटों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।

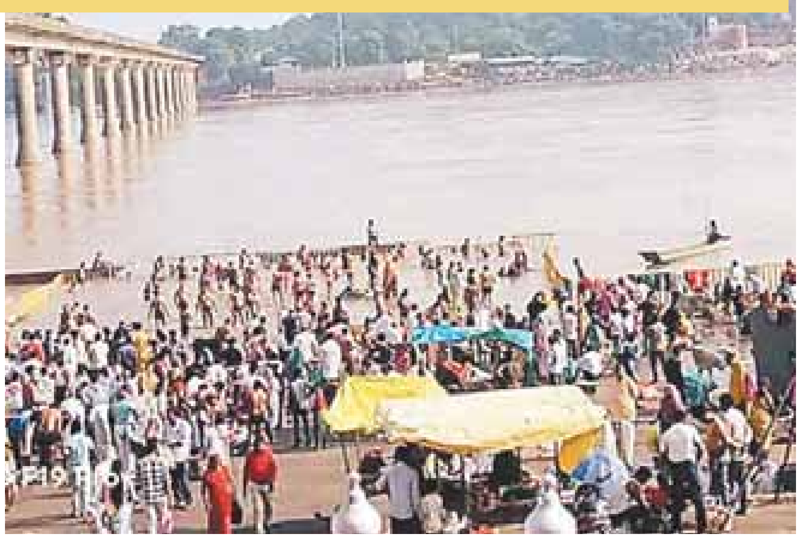

महर्षि अरविंद के स्वतंत्रता की क्रांति में योगदान की महानता जन जन तक पहुंचाएं : मोहन नागर

सुबह सवेरे सोहागपुर। महर्षि अरविंद के स्वतंत्रता की क्रांति में योगदान की महानता जन जन तक पहुंचाएं। देश की स्वतंत्रता में अनेक ऐसे वीर हैं।जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी महानता को देश के सामने लाना आवश्यक है। उक्त उद्गार मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में नर्मदापुरम में आयोजित महर्षि अरविंद की 152 जयंती के

अवसर पर जन अभियान परिषद के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन नागर ने मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। इस अवसर पर विशेष अतिथि राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया ,विशिष्ट अतिथि भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्रीमती अर्चना पुरोहित ,कवि नित्यगोपाल कटारे, नपाध्यक्ष नीतु यादव आदि मंचासीन थे। आपने आगे महर्षि अरविंद के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अतिथियों ने महर्षि अरविंद के जीवन पर सारगर्भित उद्बोधन दिए।

इसी अवसर पर भाजपा नेता विशाल गोलानी सोहागपुर ने मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष का शॉल एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत एवं सम्मान किया ।

जन अभियान परिषद के संभाग समन्वयक कौशलेश तिवारी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ । आपने जन अभियान परिषद के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

भाजपा संभागीय कार्यालय मंत्री हंस राय, ब्लॉक समन्वयक नरेन्द्र देशमुख, किशोर कड़ोले, मुकेश सोलंकी, हरीदा दायमा , विवेक मालवीय, नवांकुर संस्था के अमर भार्गव, संजय सराठे, विपिन यादव, कृष्ण कुमार झा, जितेंद्र मीना, हर्ष तिवारी, सुरेश यादव, हरीश नामदेव, नरेंद्र पटेल, राजेश गौर, अरुण राणा, साहिल तिलोटिया मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आनंद नामदेव ने किया ।आभार जिला समन्वयक पवन सहगल ने व्यक्त किया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत किया गया।

पिपरिया : गौरव सम्मान से सम्मानित हुईं राजश्री राठी

पिपरिया (निप्र)। माहेश्वरी महिला संगठन की प्रदेश सचिव को पांच प्रदेशों में श्रेष्ठ सचिव के रूप में उत्कृष्ठ कार्य करने पर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन मध्यांचल का अधिवेशन उज्जैन में हुआ। इसमें माहेश्वरी महिला संगठन की प्रदेश सचिव अनेकों सामाजिक संगठनों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली, सेवा के कार्यो में सबसे आगे रहने वाली राजश्री राठी ने आपकी अदालत कार्यक्रम में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पांच प्रदेशों में श्रेष्ठ सचिव के रूप में उत्कृष्ठ कार्य करते हुए गौरव सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर पूर्व मध्यप्रदेश के प्रदेश महामंत्री श्यामसुंदर जेठा, नर्मदापुरम जिला संरक्षिका आशा मालपानी सहित स्थानीय अध्यक्ष अरुणा मूंदडा, सचिव पिंकी राठी, प्रचार मंत्री अंजू घुरका सहित पदाधिकारी सदस्यों ने बधाईयां दी। उन्होंने कहा कि महिला संगठन के कार्यो में सहयोग की कार्यप्रणाली बेहतर कार्यशीलता व गंभीरता आपसी समन्वय बैठालकर काम करने के कारण सामाजिक कार्यो में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है।

फैक्ट्री से निकलने वाली दुर्गंध से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन

लोगों की मांग- फैक्ट्री को तत्काल बंद किया जाए

हरदा (निप्र)। हरदा जिले की टिमरनी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम छिद्गांव मेल सहित अन्य तीन चार गांवों के लोगों ने गांव के पास बनी बायो फैक्ट्री की दुर्गंध से परेशान होकर उसे हटाए जाने के लिए प्रदर्शन किया है। ग्राम छिदगांव, पिपल्या सहित आसपास के ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट की दुर्गंध से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं बुजुर्गो ओर बच्चों में अस्थमा जैसी बीमारियों का प्रभाव दिखाई दे रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि जब फैक्ट्री बनने के दौरान जब ग्रामवासियों से परमिशन ली गई थी। तब उन्हें नहीं पता था कि इतनी परेशानी होगी। वहीं खेती हर भूमि पर किस नियम के मुताबिक अनुमति दी गई है और यहां लगने वाला पानी भी नदी से लिया जा रहा है। जिससे आसपास के क्षेत्रों में जल स्त्रोत कम हो रहा है। इन सभी मांगों को लेकर ग्रामीणों की मांग है कि फैक्ट्री को यहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, नहीं तो ग्रामीणों को रहना मुश्किल हो जाएगा। उधर फैक्ट्री की सुरक्षा को मौके पर बड़ी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन के अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश दी गई, लेकिन वो फैक्ट्री को बंद करने की मांग पर अड़े रहे। इस मामले को लेकर टिमरनी एसडीएम महेश बड़ोले का कहना है कि यहां संचालित होने वाली फैक्ट्री एनजीटी की परमिशन लेकर ही संचालित हो रही है। वहीं यहां मक्का एवं चावल से प्रोडक्ट निकलता है।जिससे एथिनाल बनता है। फैक्ट्री प्रबंधन के अनुसार यह बदबू ना होकर खुशबू है।

अज्ञात बेहोश व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया

चारुवा। उपभोक्ता कल्याण समिति के सदस्यों ने रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति की जान बचाई। समिति को सूचना मिली कि गुप्तेश्वर मंदिर के सामने, टंकी के नीचे एक व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है। समिति सदस्य व पैरालीगल वालेंटियर तत्काल मौके पर पहुंचे। 108 एंबुलेंस के साथ डायल 100 को भी सूचना दी। ग्रामीणों की मौजूदगी में अज्ञात व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खिरकिया में भर्ती कराया।

नगर पालिका ने जल और संपत्ति कर बढ़ाया दुकानों का किराया चार गुना हुआ

दोनों पक्षों के पार्षदों ने विरोध किया, फिर भी 12 प्रस्ताव पास

विदिशा (निप्र)। विदिशा में शनिवार को नगर पालिका परिषद की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 प्रस्तावों पर चर्चा होना थी, जिसमें विभिन्न टैक्स को बढ़ाने के प्रस्ताव को विपक्ष के साथ-साथ सत्ताधारी दल के पार्षदों ने भी विरोध किया था। नगरपालिका की दुकानों के किराए में भी वृद्धि के विरोध में पूरा सदन एकमत था, उसके बावजूद नगर पालिका ने सभी आपत्तियों को दरकिनार कर करों में वृद्धि कर दी। दुकानों का किराया भी चार गुना बढ़ा दिया।

जानकारी के अनुसार, 12 बिंदुओं में संपत्ति कर, जल कर, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कर और सीवेज कर भी शामिल हैं। इसके अलावा नगर पालिका के आधिपत्य की दुकानों का किराया चार गुना बढ़ाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ। इन दोनों ही प्रस्तावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने भी आपत्ति जताई। इसका विरोध किया और इसे लागू न करने की मांग की थी। इसी दौरान बैठक में पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों के बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण माहौल गर्मा गया था और बैठक को स्थगित कर दिया गया था। इसके बावजूद नगर पालिका ने सभी 12 बिंदुओं के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, सभी प्रकार के करो में वृद्धि कर दी गई।

टैक्स लगाना आम जनता को बोझ तले दबाना

शासन की गाइडलाइन के अनुसार रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति कर लगेगा। जल कर को दोगुना कर दिया है। इसके साथ-साथ दुकानों के किराए को चार गुना बढ़ा दिया है। बैठक में आपत्ति करने वाले पार्षद आशीष माहेश्वरी और धर्मेंद्र यादव ने इसे नगर पालिका की मनमानी करार दिया। उन्होंने इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका आम जनता को सुविधा नहीं दे पा रही है। बावजूद टैक्स लगाना आम जनता को बोझ तले दबाना है।

दुकानदारों को चार गुना ज्यादा किराया देना होगा

वहीं पूर्व एल्डरमैन रहे रमेश अग्रवाल का कहना है कि नगर पालिका के पार्षदों और परिषद से आम जनता को काफी उम्मीद थी। लेकिन उम्मीद पूरी तरह से निराश करने वाली रही है। सड़कें खुदी हुई हैं। विकास के नाम पर कोई ऐतिहासिक काम नहीं किया गया और उसी पर टैक्स बढ़ाया जाना जनता के साथ छलावा है। नगर पालिका सीएमओ अनिल विधूवा का कहना है कि सभी 12 प्रस्तावों पर पार्षदों ने हस्ताक्षर किए हैं। जल कर विदिशा के अलावा प्रदेश के अन्य जगहों पर कई गुना हैं। विदिशा में ही इसकी वृद्धि नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर अब रजिस्ट्री के आधार पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार तय किया जाएगा। दुकानों के किराए में चार गुना वृद्धि की गई है।

गरीबी से मुक्त गांव बनाने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ी जाएगी : केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान

एक साल में तीन करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य

विदिशा (निप्र)। केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास श्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा के रविंद्र नाथ टैगोर सांस्कृतिक (ऑडिटोरियम) भवन में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के स्वतंत्र प्रभार (राज्य मंत्री) एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखन पटेल एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा देश में तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर फोकस किया है। विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गरीबी से मुक्त गांव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हर एक दीदी के चेहरे पर मुस्कान हो यही मेरा सपना है। गांव-गांव का संकल्प रहेगा गरीबी मुक्त गांव बनाया जाए। प्रधानमंत्री जी ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी द्वारा तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है अब तक देश में एक करोड़ 11 लाख से अधिक लखपति दीदियां बन गई हैं। दो करोड़ लखपति दीदियां और बनाई जाएंगी। इसके लिए सभी प्रयास भारत सरकार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने शासन की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी विस्तृत प्रकाश डाला। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि गांव का विकास, बहनों का कल्याण और किसानों का उद्धार हो इस दिशा में भारत सरकार कार्य कर रही है, महिलाओं की आर्थिक उन्नति से ही देश आगे बढ़ेगा। आज के दौर में राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं पीछे नहीं है कई महिलाएं राजनीति से जुड़कर सरपंच से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष बन गई है जो बड़े हर्ष का विषय है। आगामी निर्वाचनों में यही महिलाएं विधायक भी बनेंगी। पूर्व के समय में महिलाएं सिर्फ चूल्हा-चैका ही संभालती थी लेकिन आज के दौर में महिलाएं आर्थिक उन्नति कर लखपति दीदी बन रही हैं और अपने घर परिवार हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम विभाग के मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं विदिशा विधायक श्री मुकेश टण्डन ने भी शासन की विभिन्न महत्वकांक्षी योजनाओं तथा लखपति दीदी बनने की दिशा में केन्द्र और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यो पर विस्तृत प्रकाश डाला। इसके पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी के चित्र के साथ दीप प्रज्वलन कन्या पूजन के साथ हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान सहित अन्य अतिथियों ने स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों को हित लाभ का वितरण भी किया। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहानने स्व-सहायता समूहो की दीदीयों को छह-छह लाख रूपए के डेमो चेक प्रदाय किए।

जनजातीय विकास कार्य प्रेरक दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित हो

राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा की गई उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि जनजातीय समुदाय को विकास के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, समावेशी समाज का आधार है। राज्यपाल श्री पटेल आज राजभवन में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जनजातीय छात्र-छात्राओं के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जनजातीय विकास और कल्याण प्रयासों को प्रेरक दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया जाना

चाहिए। देश में सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य होने के कारण प्रदेश का दायित्व है कि जनजातीय विकास और कल्याण के कार्य आदर्श स्वरूप में संचालित हों। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं पी.एच.डी. छात्रवृत्तियों के प्रावधानों को केंद्र सरकार की योजनाओं के अनुसार किए जाने की जरूरत बताई है। उन्होंने जनजातीय समुदाय की मेधावी प्रतिभाओं के माध्यम से समुदाय के युवाओं और भावी पीढ़ी को प्रेरित करने की जरूरत बताई है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के साथ ही जनजातीय विषयों के अध्ययन की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। बैठक में जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री मुकेश चंद गुप्ता, प्रमुख सचिव जनजाति कार्य डॉ. ई. रमेश कुमार, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री निशांत वरवड़े, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

दिव्यांगजनों को रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़ने विशेष प्रयास होंगे: कुशवाह

जिला स्तर पर शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजनों को रोजगार के लिये प्राथमिकता दें

भोपाल। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्यान मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा है कि दिव्यांग जनों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सभी जिला कलेक्टर को जिला कार्यालयों में कैंटीन, फोटो कॉपियर टाइपिंग सेंटर जैसी रोजगार गतिविधियों में दिव्यांगजन को प्राथमिकता दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह गतिविधियां दिव्यांगजनों को समूह के रूप में भी प्रदान की जा सकती हैं। साथ ही बैंकों के माध्यम से रोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि राज्य शासन विकलांगों के पुनर्वास कार्यक्रम को प्राथमिकता के साथ कर रहा है। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चला रही है। इसमें आरक्षण और रोजगार मेला दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जहां उन्हें निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी अवसर मिलते हैं। दिव्यांगजनों को सक्षम बनाने के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इनमें विभिन्न प्रकार के तकनीकी और गैर-तकनीकी प्रशिक्षण शामिल हैं। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि जिन दिव्यांग भाइयों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिये राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता और ऋण योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। समावेशी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान राज्य में समावेशी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विशेष संस्थान भी स्थापित किए जा रहे हैं जो दिव्यांगजनों को शिक्षा और प्रशिक्षण में मदद करते हैं। इन सभी कदमों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। सरकार निरंतर इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए काम कर रही है और दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

मप्र के 14 शिक्षकों को मिलेगा राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार, टीचर्स डे पर होंगे सम्मानित

भोपाल। इस वर्ष सरकारी स्कूलों के 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें भोपाल से एक शिक्षक उच्च माध्यमिक श्रेणी में शासकीय उत्कृष्ट उमावि के व्याख्याता राजेंद्र जसूजा का नाम शामिल हैं। इस वर्ष का राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती हाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह में 14 शिक्षकों को और पिछले वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2023 के पुरस्कृत दो शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें प्राथमिक व माध्यमिक श्रेणी में आठ शिक्षकों और उच्चतर माध्यमिक श्रेणी में छह को राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। शिक्षकों को सम्मान राशि 25 हजार रुपये, शाल-श्रीफल एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। दमोह जिले के शासकीय प्राथमिक शाला देवरान टपरिया की प्राथमिक शिक्षक शीला पटेल, शाजापुर जिले के शासकीय नवीन प्रायमरी स्कूल ताजपुर के प्राथमिक शिक्षक वैभव तिवारी, ग्वालियर जिले के शासकीय माध्यमिक शाला बाडौरी मुरार के शिक्षक बृजेश कुमार शुक्ला, छिंदवाड़ा के शासकीय प्राथमिक शाला कउआखेड़ा के प्राथमिक शिक्षक राकेश कुमार मालवीय, गुना जिले के शासकीय माध्यमिक शाला समरसिंगा के प्राथमिक शिक्षक राजीव कुमार शर्मा, राजगढ़ जिले के बांगुपरा शासकीय प्राथमिक स्कूल के प्राथमिक शिक्षक सुरेश कुमार दांगी, खंडवा जिले की शा. प्राथमिक शाला झूमरखाली की शिक्षिका नीतू ठाकुर, सिवनी के शासकीय प्राथमिक शाला भीरा खंडवा के शिक्षक संजय कुमार रजक के नाम शामिल हैं। इंदौर के गुरुकुलम महू के उच्च माध्यमिक शिक्षक जगदीश सोलंकी, छिंदवाड़ा के शासकीय उत्कृष्ट उमावि की शिक्षिका अमिता शर्मा, मंदसौर के शा. बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर-2 की शिक्षिका कीर्ति सक्सेना, भोपाल के शासकीय उत्कृष्ट उमावि के व्याख्याता राजेंद्र जसूजा, उज्जैन के शासकीय कन्या उमावि सराफा की उच्च माध्यमिक शिक्षक ज्योति तिवारी, शहडोल के शासकीय एमएलबी उमावि की माध्यमिक शिक्षक अंजना द्विवेदी का नाम शामिल हैं।

अब इंदौर से 'दूर' नहीं है मुंबई...

प्रदेश के चार जिलों से होकर गुजरेगी नई रेल लाइन

भोपाल। नमस्कार, इंदौर-मनमाड़... आपने अभिवादन के कई तरीके सुने होंगे लेकिन ऐसा तरीका कम ही देखा सुना गया है। इस योजना से मध्य प्रदेश के चार और महाराष्ट्र के दो रेल वंचित जिलों को लाभ मिलेगा। इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना की मंजूरी मिलने

- एमपी के हजारों गांव के लाखों लोग पहली बार देखेंगे ट्रेन
- इंदौर-मनमाड़ लाइन की मंजूरी के बाद लोगों में छाई खुशी

के बाद एमपी के राजनेताओं में खुशी की लहर है। सभी लोग अपनी भावना को सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे हैं। क्षेत्र के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने भी 18036 करोड़ की 309 किमी लंबी इस रेल परियोजना की स्वीकृति मिलने पर अपनी कोशिशों को शेयर किया है। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि यह मुद्दा 2018 में मुंबई जेएनपीए- इंदौर परियोजना के रूप में फली भूत होते दिखाई दिया था। इस दौरान तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल, परिवहन व जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच एमओयू साइन हुआ था। लेकिन विभिन्न कारणों के चलते योजना खटाई में पड़ गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद सभी हतोत्साहित हो गए थे। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में रेल फिर से सपना प्रतीत होने लगा था। लेकिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने फिर से कोशिशें की। उन्होंने बताया कि दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उनके पड़ोसी हैं और इस नाते अक्सर मुलाकात होती रहती है। वे लगातार उन्हें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस परियोजना के विषय में बताते रहे। हालात तो यह हो गए कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब भी उनसे मिलते, वह उन्हें 'नमस्कार इंदौर-मनमाड़' से अभिवादन करने लगे। डॉ सोलंकी ने बताया कि कल भी इस परियोजना की स्वीकृति के बाद रेल मंत्री से फोन पर चर्चा हुई और उन्हें 105 साल पुरानी इस मांग के लिए आभार दिया। इस फोन चर्चा की वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की है। उन्होंने बताया कि 'जनजातीय गौरव कॉरिडोर' योजना के तहत नवीन रेल लाइनों के विस्तार के अंतर्गत इस परियोजना की स्वीकृति हुई है। उधर लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल ने भी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 2021 के बाद से लगातार लोकसभा समेत विभिन्न फोरमों पर इस परियोजना के लिए मांग उठाई थी। परियोजना को लेकर क्षेत्र से जुड़े सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना सन 2028- 29 तक पूरी हो जाएगी। वहीं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने कहा कि इससे आदिवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। वहीं, 2018 में एमओयू में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इस परियोजना से इंदौर मुंबई की दूरी कम हो जाएगी। इसके साथ-साथ क्षेत्र के लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इंदौर वेस्टर्न रेलवे का अंतिम स्टेशन था लेकिन अब इसका एक्सटेंशन हो गया। अब यह भारत के महत्वपूर्ण रेल जंक्शन्स में शामिल हो सकेगा। अब इस परियोजना से मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य तीन जिलों बड़वानी, खरगोन, धार के अलावा इंदौर क्षेत्र को लाभ मिलेगा। इस परियोजना से आकांक्षी बड़वानी जिले के 80 किलोमीटर क्षेत्र में रेल सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

30 नए स्टेशन बनेंगे, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे आकांक्षी जिले बड़वानी को बेहतर संपर्क मिलेगा। नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1,000 गांवों और लगभग 30 लाख आबादी को संपर्क मिलेगा। बड़वानी जिले में भी डी श्रेणी के नौ स्टेशन बनाए जाएंगे। इसमें सेंधवा, ओजार, जुलवानिया, लिंगवा, खजूरी, कुंडलमल और ठीकरी शामिल हो सकते हैं। खरगोन जिले में निमरानी और धार में धामनोद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं, परियोजना देश के पश्चिमी/दक्षिण-पश्चिमी हिस्से को मध्य भारत से जोड़ने वाला छोटा रास्ता उपलब्ध कराकर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी। इससे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित उज्जैन-इंदौर क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन/धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना से पीथमपुर ऑटो क्लस्टर (90 बड़ी इकाइयां और 700 छोटे और मध्यम उद्योग) को जेएनपीए के गेटवे पोर्ट और अन्य राज्य बंदरगाहों से सीधा संपर्क मिलेगा। परियोजना मध्य प्रदेश के बाजरा उत्पादक जिलों और महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक जिलों को भी सीधा संपर्क प्रदान करेगी, जिससे देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में इसके वितरण में सुविधा होगी। कृषि उत्पादों, उर्वरक, कंटेनर, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट, पीओएल आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है। क्षमता वृद्धि कार्य के परिणामस्वरूप लगभग 26 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। इस परियोजना की स्वीकृति के बाद बड़वानी जिले में हर्ष की लहर व्याप्त हो गई। कई जगह आतिशबाजी कर खुशियां मनाई गई।

'अष्टछाप के अर्वाचीन कवि' का लोकार्पण आज शाम

भोपाल। 'हम विक्रम' द्वारा पंकज पाठक के सम्पादन में देश के आठ पत्रकारों की कविताओं के संकलन–'अष्टछाप के अर्वाचीन कवि' का लोकार्पण वरिष्ठ समाजसेवी हेमंत मुक्तिबोध के मुख्य आतिथ्य में 4

सितंबर 2024, बुधवार को दुष्यंत संग्रहालय में शाम 5 बजे आयोजित किया गया है। अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार उमेश त्रिवेदी करेंगे और सारस्वत अतिथि हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव । कवि हैं–उमेश त्रिवेदी, पंकज पाठक, शिल्पा शर्मा, अजय बोकिल, कौशल किशोर चतुर्वेदी, आरिफ़ मिर्ज़ा, डॉ वंदना शुक्ला और आरती शर्मा । कार्यक्रम का संचालन अंतरराष्ट्रीय ख्याति के हिंदी-सेवी और लेखक डॉ. जवाहर कर्नावट करेंगे एवं उर्दू के मशहूर शायर और एंकर बद्र वास्ती आभार मानेंगे । पुस्तक का आवरण प्रख्यात कलाकार प्रो. आलोक भावसार एवं हरिओम तिवारी ने तैयार किया है । यह संकलन भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति धारा के महान अष्टछाप के कवियों को समर्पित किया है । पिछले एक वर्ष में पंकज पाठक के संपादन में प्रकाशित यह तीसरा साझा-संकलन है ।

भोपाल शहर के एसडीएम-तहसीलदार बदले

कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई करने वाले एसडीएम को शहर का जिम्मा; खरे एमपी नगर लौटे

भोपाल। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को दो एसडीएम और चार तहसीलदारों को इधर से उधर किया। कोचिंग सेंटारों पर सख्त कार्रवाई करने वाले एमपी नगर एसडीएम आशुतोष शर्मा को शहर का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं, एलके खरे की वापसी हुई है। एसडीएम शर्मा ने पिछले दो महीने में अंदर एमपी नगर की कई कोचिंग क्लॉसेस पर कार्रवाई की है। फायर सेफ्टी और सुरक्षा इंतजाम नहीं मिलने पर कोचिंग संचालकों को नोटिस भी जारी किए थे। वहीं, बैसमेंट भी सील कर दिए थे। कोचिंग संचालकों को नोटिस भी दिए गए थे। जिसकी मियाद मंगलवार को खत्म हो गई। इसी बीच शर्मा को शहर वृत्त और शहर वृत्त से खरे को एमपी नगर में भेज दिया गया। खरे पहले भी एमपी नगर एसडीएम रह चुके हैं। उन्होंने फायर सेफ्टी के इंतजामों को लेकर लगातार

राजधानी में थम नहीं रहा बारिश का दौर, फिर झमाझम

सुबह से शुरू हुई बारिश, अब तक हो चुकी 42 इंच बारिश

भोपाल। राजधानी भोपाल में आज, मंगलवार सुबह से ही बारिश का दौर चल रहा है। सुबह 10 बजे कोलार इलाके में तेज बारिश हुई, जबकि एमपी नगर, करोंद, बैरसिया रोड, रायसेन रोड, अयोध्या बायपास समेत कई जगहों पर पानी गिरा। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे पहले रविवार और सोमवार को लगातार दो दिन तक भोपाल के सभी डैम के गेट एक साथ खुले रहे। कलियासोत-केरवा के 2 और भदभदा-कोलार डैम का एक-एक गेट खुला रहा। डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने ने डैम में पानी की आवक जारी रही। हालांकि, मंगलवार सुबह गेट बंद कर दिए गए। दूसरी ओर, पूरा जिला तरबतर हो गया है। अब तक करीब 42 इंच बारिश हो चुकी है, जो सीजन की 111 प्रतिशत है। सितंबर के महीने में भोपाल में करीब 7 इंच बारिश होने का ट्रेंड है। अबकी बार लगातार दो दिन में डेढ़ इंच बारिश हो चुकी है। रविवार रात में भदभदा डैम से छोड़ा गया पानी कलियासोत डैम में पहुंचा। जिससे इसके भी दो गेट खुले रहे। केरवा डैम के दो गेट खुले रहे। भोपाल के पास कोलार डैम का भी 1 गेट खुला हुआ। डैम प्रभारी हर्षा जैनवाल ने बताया कि डैम फुल हो गया है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से गेट खुला रहा। मंगलवार को सभी डैम के गेट बंद हो गए। सितंबर में अच्छी बारिश होती है। 65 साल पहले वर्ष 1961 में पूरे महीने 30.2 इंच बारिश होने का रिकॉर्ड है। अबकी बार भी सितंबर की शुरुआत तेज बारिश से हुई है। इस मानसून सीजन में भोपाल में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। भोपाल की सामान्य बारिश 37.6 इंच है, जबकि इस बार करीब 42 इंच पानी गिर गया है। यानी, 111 प्रतिशत बारिश हो चुकी है। जून के बाद जुलाई और अगस्त में रिकॉर्ड बारिश हुई। यही कारण है कि बारिश का आंकड़ा बढ़ता गया। सितंबर में बारिश के आंकड़ों पर नजर डाले तो वर्ष 2014 से 2023 में 2 बार ऐसा हुआ, जब पूरे महीने 12 इंच से ज्यादा पानी गिरा। 10 साल में सबसे ज्यादा बारिश 2019 में 22.2 इंच हुई थी। पिछले साल 12.8 इंच बारिश दर्ज की गई थी। इस बार डेढ़ इंच पानी गिर चुका है। जून में मानसून एक्टिव होता है, जबकि सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में विदाई होने लगती है। इस महीने भारी बारिश की स्थिति तब पैदा होती है, जब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र ओडिशा तट को पार करते हुए पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़कर प्रदेश में एक्टिव होता है। सितंबर में बारिश के साथ तेज आंधी चलती है। वहीं, तीखी धूप भी खिलती है। इस वजह से पारा 37 डिग्री के पार पहुंच सकता है।

पीएम किसान सम्मान निधि

वन अधिकार पत्र धारकों को मिले शत-प्रतिशत लाभ

वन मंत्री ने की वन विभाग की समीक्षा, किसान क्रेडिट कार्ड पर भी चर्चा

भोपाल। वन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री श्री रामनिवास रावत ने वन अधिकार पत्र धाराकों को शासन की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं किसान क्रेडिट कार्ड का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वनों में निवास करने वाले अनूसुचित जनजातीय वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर रूपये 3 हजार से बढ़ाकर 4 हजार प्रति मानक बोरा कर दी गई है। जिससे वनवासियों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण के पारिश्रमिक के रूप में 660 करोड़ की राशिवितरित की गई है। मंत्री श्री रावत ने कहा कि बांस रोपण को बढ़ावा दिया जाये और इसके लिये अधिक से अधिक कृषकों को बांस लगाने के लिये प्रेरित किया

जाये। मंत्री रावत ने कहा कि वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन करने की कार्रवाई की जाये। इसके लिये समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाकर समस्त कलेक्टरों को निर्देश जारी करें। मंत्री श्री रावत ने बताया कि एक 'एक पेड़ माँ के नाम अभियान' के अंतर्गत 6.30 करोड़ पौधा रोपण लक्ष्य के विरूद्ध 5.47 पौधे रोपित किये गये है। मंत्री श्री रावत ने कहा कि अनुभुति कार्यक्रम के अंतर्गत 1151 शिविरों में 2287 शैक्षणिक संस्थानों के 1.47 लाख विद्यार्थियों एवं 8006 शिक्षकों को वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि चीता परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत गांधी सागर अभ्यारण, मंदसौर में चीता लाने की तैयारियाँ शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। इसके लिये हमें वनों में पुख्ता इंतेजाम करने होंगे। मंत्री श्री रावत ने बाघ प्रबंधन के लिये अधिकारियों को निर्देश दिये उन्होंने कहा कि बाघ की संख्या में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है। बाघ संरक्षण के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिये की माधव राष्ट्रीय उद्यान एवं रातापानी अभ्यारण को टाईगर रिजर्व घोषित करने के कार्रवाई करे। मंत्री श्री रावत ने वन विभाग की सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में वन विभाग के एसीएस श्री अशोक वर्णवाल, वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।